सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

*" बहुत आसान होता है किसी पर उंगली उठाना,
लेकिन बहुत मुश्किल होता है किसी को उठाने के लिए
उसकी उंगली को पकड़ना...!! "*

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–96 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, रविवार 26 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए देश में 95 करोड़ की एंट्री! ईडी का बड़ा खुलासा

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े वित्तीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया है कि विदेशी बैंक डेबिट कार्ड के जरिए भारत में करोड़ों रुपये की संदिग्ध एंट्री कराई जा रही थी। 18 और 19 अप्रैल 2026 को देश के कई राज्यों में छह स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाकर इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया।

ईडी मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार यह कार्रवाई टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) नामक संगठन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर की गई है,

जो भारत में FCRA के तहत पंजीकृत नहीं है, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर फंडिंग और खर्च के संकेत मिले हैं।

विदेशी बैंक कार्ड से कैश निकासी का खेल

जांच में सामने आया कि अमेरिका के Truist Bank से जुड़े डेबिट कार्ड भारत लाकर विभिन्न राज्यों के एटीएम से बार-बार भारी मात्रा में कैश निकाला जा रहा था। इस नकदी का उपयोग TTI से जुड़ी गतिविधियों में किया जा रहा था।

ईडी को संदेह है कि यह पूरा ऑपरेशन एक संगठित नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था, जिसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं।

एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी, 24 विदेशी कार्ड बरामद

मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ जब माइका मार्क नामक व्यक्ति को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद किए गए। यह कार्रवाई ईडी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) के आधार पर की गई।

नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंचा पैसा

जांच में यह भी सामने आया कि छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी इन कार्ड्स के जरिए कैश निकाला गया। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 6.5 करोड़ रुपये की निकासी का रिकॉर्ड सामने आया है।

ईडी के अनुसार, इस तरह की पैरेलल कैश-बेस्ड इकोनॉमी देश की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि इससे अवैध गतिविधियों को फंडिंग मिलने की आशंका बढ़ जाती है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होता था हिसाब-किताब

पूरे नेटवर्क में निकाले गए पैसों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे विदेश से संचालित किया जा रहा था। इससे संकेत मिलते हैं कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा था। ईडी की कार्रवाई में 25 विदेशी डेबिट कार्ड, करीब 40 लाख रुपये नकद, डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज, बरामद किए गए हैं।

95 करोड़ रुपये का ट्रेल

जांच एजेंसी के अनुसार नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इस तरीके से करीब 95 करोड़ रुपये भारत में लाए गए। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

भिलाई में ब्लैकमेलिंग का बड़ा खुलासा: स्पर्श अस्पताल से 20 लाख की मांग, आरोपी के खिलाफ अपराध हुआ दर्ज

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शहर में अस्पतालों को निशाना बनाकर उगाही करने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। एसबीएस अस्पताल के बाद अब रामनगर सुपेला स्थित स्पर्श अस्पताल के संचालक ने भी गुरुमीत सिंह वाधवा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार आरोपी ने अस्पताल प्रबंधन से 20 लाख रुपये की मांग करते हुए झूठे केस में फंसाने और अस्पताल बंद कराने की धमकी दी।

स्पर्श अस्पताल के महाप्रबंधक अखिल मडामे ने सुपेला थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि सुंदर नगर निवासी गुरुमीत सिंह वाधवा नवंबर 2025 में अस्पताल पहुंचा था। उसने खुद को फोर्ब्स इंटरनेशनल मैगजीन का एडिटर बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ फोटो दिखाकर प्रदेश के अस्पतालों की जांच के लिए अधिकृत होने का दावा किया।

प्रबंधन के अनुसार आरोपी दो बार अस्पताल आया और कथित जांच के नाम पर दबाव बनाता रहा। उसने ऑक्सीजन प्लांट, पर्यावरण नियम और भवन से जुड़ी खामियों का हवाला देकर लगातार धमकियां दीं। इतना ही नहीं, आरोपी मोबाइल कॉल के जरिए भी प्रबंधन को डराता रहा और अस्पताल की पार्किंग तक बंद कराने की बात कहता रहा।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि जनवरी 2026 में आरोपी अस्पताल के महाप्रबंधक के केबिन में पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा और सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाकर अस्पताल को घेरने की धमकी दी। प्रबंधन का आरोप है कि आरोपी हर संभव तरीके से दबाव बनाकर रकम वसूलने की कोशिश कर रहा था।

हालांकि शुरुआत से ही अस्पताल प्रबंधन को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। सुपेला पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है। यह घटनाक्रम सामने आने के बाद शहर के स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप मच गया है। लगातार सामने आ रहे मामलों से यह संकेत मिल रहा है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से अस्पतालों को निशाना बनाकर उगाही का प्रयास कर रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित मामलों की भी जांच कर रही है।

आईपीएल खेल, दुर्ग में अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़

ऑनलाइन सट्टा में करोड़ों का खेल, 5 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

आईपीएल सीजन के दौरान ऑनलाइन सट्टे के काले कारोबार पर दुर्ग पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो गोवा, रायपुर, भिलाई सहित कई राज्यों से मिलकर संगठित तरीके से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे।

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह गिरोह फर्जी सिम, म्यूल अकाउंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कॉल के जरिए नेटवर्क संचालित कर रहा था। रोजाना 10 से 15 लाख रुपये का लेनदेन और हर महीने 4 से 5 करोड़ रुपये तक के अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा था।

थाना सिटी कोतवाली में दर्ज प्रकरण की विवेचना के दौरान पहले 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद साइबर और वित्तीय विश्लेषण के जरिए पुलिस गिरोह के ऊपरी स्तर तक पहुंची और 5 अन्य मुख्य सदस्यों को दबोच लिया। आरोपियों का नेटवर्क छत्तीसगढ़ के साथ-साथ गोवा और अन्य राज्यों तक फैला हुआ था।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, 76 एटीएम कार्ड, 45 बैंक पासबुक, 10 चेकबुक, 5 सिम कार्ड और

2.70 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं। यह पूरा नेटवर्क डिजिटल माध्यम से संचालित हो रहा था, जिससे सट्टे का कारोबार बेहद संगठित और खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था।

गिरफ्तार आरोपियों में रायपुर, प्रयागराज, गोंदिया और भिलाई के युवक शामिल हैं, जो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस अवैध धंधे से जुड़े थे। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार और भी राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच जारी है।

दुर्ग पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि ऑनलाइन सट्टा और साइबर अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आईपीएल जैसे बड़े आयोजनों के दौरान ऐसे गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए आम नागरिकों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है। यह कार्रवाई न केवल सट्टा कारोबार पर करारा प्रहार है, बल्कि यह भी संकेत है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फैल रहे अपराधों पर पुलिस अब तकनीकी स्तर पर भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है।

बुजुर्ग ने युवक को कुल्हाड़ी से काटा, खुर्सीपार में खून से लथपथ मिली लाश

भिलाई। दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। 30 वर्षीय युवक की मोहल्ले के एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सड़क किनारे युवक की गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। मोहल्ले के लोग घायल युवक को अस्पताल ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र वार्ड 44 लक्ष्मीनारायण नगर की है। मृतक युवक का नाम विक्रम सोना (30) बताया जा रहा है। विक्रम सोना ट्रांसपोर्ट नगर में हाइड्रा चलाने का काम करता था। रविवार की सुबह विक्रम का मोहल्ले के ही 60 वर्षीय मुरली उर्फ मुच्छू से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मुच्छू ने कुल्हाडी से विक्रम सोना पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले से विक्रम सोना गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं बेसुध होकर गिर गया। इसके बाद मुच्छू वहां से फरार हो गया। मोहल्ले वालों ने घटना की सूचना खुर्सीपार पुलिस को दी और घायल विक्रम को अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही विक्रम सोना की मौत हो गई। इधर खुर्सीपार पुलिस ने घटना के बाद आरोपी मुच्छू को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद लक्ष्मीनारायण नगर में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले आरोपी मुच्छू के बेटे से विक्रम का विवाद हुआ था और रविवार को मुच्छू से विवाद हुआ। फिलहाल हत्या का कारण क्या है कि इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है।

भिलाई निगम में टकराव तेज: महापौर ने आयुक्त के अधिकारों पर लगाई रोक, नोटशीट पर दिया सख्त अभिमत

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर और आयुक्त के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। आयुक्त द्वारा महापौर परिषद की बैठक बुलाने के लिए जारी नोटशीट पर महापौर नीरज पाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि आयुक्त को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई या बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है।

महापौर नीरज पाल ने अपने अभिमत में उल्लेख किया है कि 25 मार्च 2026 को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 54 (2) के तहत आयुक्त को सर्वसम्मति से पद से हटा दिया गया था। ऐसे में उक्त संकल्प के बाद आयुक्त के पास निगम अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उपयोग करने का अधिकार नहीं बचता।

महापौर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शासन से अंतिम आदेश आने तक आयुक्त अपने कार्यों से विमुख रहेंगे और इस अवधि में उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय शून्य माने जाएंगे। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि आयुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक आहूत की जाती है या प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते हैं, तो यह सामान्य सभा के पारित प्रस्ताव का उल्लंघन माना जाएगा।

इस घटनाक्रम ने निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर उत्पन्न इस गतिरोध का सीधा असर शहर के विकास कार्यों और योजनाओं पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

फिलहाल निगाहें शासन के अगले फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि निगम में अधिकारों का संतुलन किसके पक्ष में जाता है।

मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का मामला: आरोपी हिरासत में

भिलाई। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के ग्राम पुरैना में पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की गंभीर घटना सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2), 296, 115(2), 351(3) एवं POCSO Act की धारा 4 एवं 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आरोपी की पहचान किशोर चौहान (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने घटना के बाद तत्काल हिरासत में ले लिया। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही हैं। साथ ही पीड़ित बच्ची के संरक्षण एवं परामर्श के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वेदांता हादसा: 25 मौतों के बाद बचाव की राजनीति पर घमासान

जांच की निष्पक्षता पर उठे बड़े सवाल

नई दृष्टिबिंदु / सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने अब राजनीतिक और औद्योगिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 25 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद यह मामला केवल एक औद्योगिक हादसा नहीं, बल्कि जवाबदेही और प्रभावशाली लॉबी के दबाव की आशंकाओं के बीच घिर गया है।

प्रारंभिक जांच और स्थानीय सूत्रों के अनुसार संयंत्र में तकनीकी खामियों के संकेत पहले से मौजूद थे। आरोप है कि संभावित खतरे के बावजूद उत्पादन जारी रखा गया। यदि यह बात जांच में साबित होती है, तो यह हादसा लापरवाही का गंभीर मामला बन सकता है, जिसमें जिम्मेदारी तय करना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

जैसे-जैसे जांच की दिशा शीर्ष प्रबंधन की ओर बढ़ती दिखी, वैसे-वैसे बचाव के स्वर भी तेज हो गए। अनिल अग्रवाल को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि कंपनी के चेयरमैन का दैनिक संचालन में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए उन्हें सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

इसी बीच उद्योगपति नवीन जिंदल खुलकर समर्थन में सामने आए हैं। इस समर्थन ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। साथ ही यह भी चर्चा है कि अन्य बड़े उद्योगपति भी पर्दे के पीछे माहौल बनाने में सक्रिय हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

स्थानीय स्तर पर भी उठी आवाज

जांजगीर-चांपा क्षेत्र के सांसद कमलेश

जांगड़े ने निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित न रह जाए।

यह घटना 2009 के BALCO Chimney Collapse 2009 की याद दिला रही है, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन वर्षों बाद भी न्याय अधूरा रह गया। इसी कारण अब लोगों में यह डर गहरा गया है कि कहीं यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में न चला जाए।

मानवाधिकार आयोग सख्त, रिपोर्ट तलब

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोषियों पर कार्रवाई, पीड़ितों को मुआवजा और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पर पूरी पारदर्शिता जरूरी है।

सरकार के निर्देश, लेकिन सवाल कायम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुआवजे की घोषणा और जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है—क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएगी या प्रभावशाली लोगों का दबाव इसकी दिशा तय करेगा?

श्रमिक संगठनों का पलटवार

दूसरी ओर श्रमिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब मुनाफे का श्रेय शीर्ष नेतृत्व लेता है, तो ऐसी त्रासदी में जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि प्रभावशाली नेटवर्क के जरिए जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, जिससे असली दोषियों तक कार्रवाई न पहुंचे।

न्याय बनाम प्रभाव की परीक्षा

25 मजदूरों की मौत ने इस घटना को न्याय व्यवस्था और शासन की विश्वसनीयता की सीधी परीक्षा बना दिया है। अब पूरा प्रदेश यही देख रहा है कि क्या इस बार जिम्मेदारी शीर्ष तक तय होगी या फिर एक और बड़ा हादसा केवल आंकड़ों में सिमटकर रह जाएगा।

नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियाँ प्रारंभ

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

आगामी नेशनल लोक अदालत को अधिकतम सफल एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में तैयारियाँ तेजी से संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में न्यायालय परिसर स्थित सभागार में विभिन्न हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन कर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसी कड़ी में प्रथम बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग की अध्यक्षता में जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण के साथ आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी न्यायाधीश अपने-अपने न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करें तथा पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विवाद समाधान हेतु प्रेरित करें। साथ ही प्री-सीटिंग हेतु जारी

नोटिसों की समयबद्ध एवं प्रभावी तामिली सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

विशेष रूप से राजीनामा योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, बैंक, बीमा, मोटर दुर्घटना दावा, धारा 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत एवं अन्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण हेतु संवेदनशील, संवादात्मक एवं सकारात्मक काउंसलिंग दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा अधिवक्ताओं एवं संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर अधिकतम प्रकरणों के निराकरण को सुनिश्चित किया जाए।

तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु द्वितीय बैठक का आयोजन मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरणों से संबंधित हितधारकों के साथ किया गया, जिसमें मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीशगण, आवेदक एवं बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण तथा बीमा कंपनियों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निस्तारण हेतु विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान बीमा कंपनियों के अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे लोक अदालत के दिन सक्षम प्राधिकारी के रूप में उपस्थित रहकर व्यवहारिक एवं न्यायोचित समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही अधिवक्तागण से अपेक्षा की गई कि वे पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराते हुए समझौता प्रक्रिया में सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक अदालत की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में सीजेएम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, विशेषकर धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं अन्य राजीनामा योग्य मामलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत हेतु तैयार करें। साथ ही पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय के लाभों से अवगत कराते हुए उन्हें समझौते के लिए प्रेरित करने पर विशेष बल दिया गया।

खास खबर

मानवता की मिसाल : दम्पति ने किया रक्तदान, जरूरतमंद को मिला जीवनदान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए नगर पंचायत उतई निवासी चंदू देवांगन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवांगन ने एक बार फिर स्वैच्छिक रक्तदान कर जरूरतमंद मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। दम्पति के इस सराहनीय कदम की क्षेत्रभर में प्रशंसा हो रही है। जानकारी के अनुसार, एक निजी एवं शासकीय अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। सूचना मिलते ही देवांगन दम्पति बिना विलंब अस्पताल पहुंचे और ब्लड बैंक में रक्तदान कर मरीज के उपचार में सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि यह दम्पति पहले भी कई बार आपात परिस्थितियों में रक्तदान कर चुके हैं।

इस अवसर पर चंदू देवांगन ने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता और यह केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और निःसंकोच रक्तदान करें, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि मानसिक संतोष मिलता है। वहीं, श्रीमती किरण देवांगन ने महिलाओं से भी आगे आने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान के माध्यम से किसी के परिवार को नई जिंदगी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय समाजसेवियों एवं ब्लड बैंक प्रभारी ने दम्पति के इस सेवाभाव की सराहना करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में अक्सर रक्त की कमी हो जाती है, ऐसे में जागरूक नागरिकों का आगे आना बेहद आवश्यक है।

मोहरों की बिसात पर शुरू हुई बुद्धिमत्ता की जंग

जिला स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप का हुआ भव्य आगाज

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

25 अप्रैल 2026 जिला शतरंज संघ, दुर्ग द्वारा मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिलाई के विशेष सहयोग से दो दिवसीय जिला स्तरीय अंडर-7 एवं अंडर-11 शतरंज चैंपियनशिप का शनिवार को गरिमामय शुभारंभ हुआ। शतरंज की बिसात पर अपनी चालों से लोहा मनवाने के लिए जिले भर के नन्हे खिलाड़ी उत्साह के साथ जुटे हैं।

कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाजसेवी मुख्य अतिथि श्री कैलाश जैन बरमेचा और अध्यक्ष डॉ. अनुराग बख्शी (डेंटल स्पेशलिस्ट) ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शतरंज संघ के सचिव तुलसी सोनी एवं इंटरनेशनल आर्बिटर रॉकी देवांगन उपस्थित रहे।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य अतिथि श्री कैलाश जैन बरमेचा ने कहाः "ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही बच्चों के भीतर छिपी हुई नैसर्गिक प्रतिभा निखरकर सामने आती है। खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक अनुशासन भी सिखाते हैं। जिला शतरंज संघ का यह प्रयास सराहनीय है और मैं खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन देता हूँ।"

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. अनुराग बख्शी ने शतरंज को 'दिमाग की कसरत' बताते हुए एकाग्रता बढ़ाने में इसे सर्वोत्तम खेल बताया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि कैलाश जैन बरमेचा एवं डॉ अनुराग बख्शी ने शतरंज की चाल चलकर स्पर्धा का उद्घाटन किया। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने तकनीकी जानकारी देते हुए बताया किः कुल खिलाड़ीः 55 वर्गः अंडर-7 (20 खिलाड़ी) एवं अंडर-11 (35 खिलाड़ी)। चयन प्रक्रियाः दोनों वर्गों से शीर्ष 2 बालक एवं 2 बालिकाओं का चयन आगामी राज्य स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में सचिव तुलसी सोनी ने स्वागत भाषण दिया, जबकि मंच संचालन ईश्वर सिंह राजपूत और आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष दिनेश जैन ने किया। इस दौरान अनिल शर्मा, मोरध्वज चंद्राकर, दिव्यांशु उपाध्याय, टिकेश्वर साहू, छाया नोर्गे, संगीता, जिज्ञासा, मोनिका और अंजली टोप्पो सहित संघ के अनेक पदाधिकारी सक्रिय रहे।

स्पर्धा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल आर्बिटर रॉकी देवांगन (चीफ आर्बिटर), फीडे आर्बिटर अनिल शर्मा और सीनियर नेशनल आर्बिटर दिव्यांशु उपाध्याय अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

नाभिकीय रसायन पर विशेष अतिथि व्याख्यान का किया गया आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शैलदेवी महाविद्यालय अंडा में 23 अप्रैल 2026 को विज्ञान विभाग द्वारा नाभिकीय रसायन विषय पर एकदिवसीय विशेष अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग की सहायक प्राध्यापक डॉ. अल्का बंछोर रहीं।

अपने उद्बोधन में डॉ. अल्का बंछोर ने नाभिकीय रसायन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि यह विज्ञान परमाणु के नाभिक से संबंधित गुणों, परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन करता है। उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल, मैजिक नंबर एवं डबल मैजिक नंबर, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, अल्फा, बीटा और गामा कणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तथा श्रृंखला अभिक्रिया की प्रक्रिया को भी विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट किया।

डॉ. बंछोर ने नाभिकीय रसायन के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग, नाभिकीय ताप संयंत्रों में इसकी भूमिका तथा ऊर्जा उत्पादन में इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। उनका व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा, जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के. एन. मिश्रा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्राचार्य ने इस रोचक एवं उपयोगी व्याख्यान के सफल आयोजन हेतु विज्ञान विभाग के समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उत्कृष्ट कार्य करने पर रेलवे ने किया दीपक का सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल एवं ऑल इंडिया एस.सी.एस.टी. इलेक्ट्रिक लोको शेड (ईएलएस) चरोदा शाखा ने विगत दिनों बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया। इस दौरान ईएलएस चरोदा में पदस्थ रेलवे कर्मी दीपक कुमार को रक्तदान के माध्यम से मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि दीपक कुमार न सिर्फ रक्तदान करते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहे हैं। उनके इस प्रयास से अनेक लोगों को जीवनदान मिला है।

चिखली चौक में अवैध पशु परिवहन का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले में अवैध पशु परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चिखली चौक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक पिकअप वाहन को रोककर जांच की, जिसमें 6 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर ले जाया जा रहा था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी युवराज साहू की सूचना पर 23 अप्रैल 2026 की रात चिखली चौक में वाहन क्रमांक CG 05 D 1007 को रोका गया। जांच के दौरान पाया गया कि वाहन में मवेशियों को बिना चारा-पानी के अमानवीय तरीके से भरा गया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की

धारा 4 एवं 6 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत मामला दर्ज किया है।

गिरफ्तार आरोपियों में निर्मल मनेश्वर (38), तुलसीराम नागेश्वर (60), जयपाल नागेश्वर (43) और भगतराम खरे (43) शामिल हैं, जो मध्यप्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिले के निवासी हैं। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन और 6 मवेशी (2 पड़वा, 3 पड़िया और 1 बछिया) जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 2 लाख 32 हजार रुपये आंकी गई है।

इस कार्रवाई में चिखली चौकी पुलिस और पेट्रोलिंग टीम की सतकर्ता महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने समय रहते संदिग्ध वाहन को पकड़कर अवैध परिवहन का खुलासा किया। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि पशु क्रूरता या अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

बजरंग दल की पहल लाई रंग, निजी स्कूलों की नहीं चलेगी अब मनमानी

कार्यवाही में लापरवाही नही किए जाएंगे बर्दाश्त-रतन यादव

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी और अनियमितताओं के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग गंभीर नजर आ रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के नाम दुर्ग कलेक्टर को सौंपे गए मांगपत्र को स्कूल शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लेते हुए कई मांगों पर अपनी सहमति जताई है और प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है। इस जांच टीम को छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा विद्यार्थी और पालक हितैषी 12 बिंदुओ पर मांगपत्र सौंपा गया है। मांगपत्र में अत्यधिक गर्मी के दौरान स्कूल संचालन, फीस वसूली, ड्रेस और किताबों में बदलाव, प्रोजेक्ट के नाम पर आर्थिक दबाव, वाषिकीत्सव शुल्क, शिक्षकों को कम वेतन देने, स्कूल में प्रवेश के दौरान प्रतिवर्ष डेवलपमेंट फीस वसूली पर विरोध जताया गया है। छत्तीसगढ़ बजंरग दल के इस पहल से अब

विद्यार्थियों और अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमानी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। यह बातें छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने शनिवार को दुर्ग में मीडिया से चर्चा में कही। इस दौरान छत्तीसगढ़ बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष गौतम जैन, प्रदेश मंत्री विकास ठाकुर, प्रदेश महाविद्यालय प्रमुख रोहित सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन राजपूत, प्रदेश सह मंत्री बबलू सिंह, विभाग संयोजक कुशल तिवारी, विभाग सहसंयोजक लक्ष्मण यादव, विभाग गौ रक्षा प्रमुख कुलेश्वर यादव, जिला अध्यक्ष रवि भारती, जिला मंत्री देवाशीष घोष, जिला संयोजक अश्मित साहनी, जिला अध्यक्ष भिलाई विनोद सिंह, नगर मंत्री सवर्जीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रिंस राजपूत, नगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार मौजूद रहे। चर्चा में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी और अनियमितता के खिलाफ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, दुर्ग कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थी और अभिभावक हितैषी मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया गया था। इन मुद्दों को स्कूल शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिससे अब निजी स्कूलों की मनमानी से विद्यार्थियों और अभिभावकों को निश्चित रुप से राहत मिलेगी। श्री यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से कहा कि हर वर्ष 1 अप्रैल से स्कूल शुरू कर निजी स्कूल फीस, किताब, कॉपी, ड्रेस और परिवहन शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। अनुमान के अनुसार दुर्ग जिले में करीब 85 हजार विद्यार्थियों से लगभग 75 करोड़ रुपये तक की वसूली होती है। वहीं गर्मी बढ़ने पर विरोध के बाद ही स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए जाते हैं। किताबों के प्रकाशक बदलने और निर्धारित दुकानों से किताब खरीदने का निजी स्कूल दबाव बनाते है। जो अभिभावकों पर आर्थिक बोझ होता है। इसके अलावा बार-बार ड्रेस कोड बदलने, प्रोजेक्ट बनवाने के नाम पर हजारों रुपये खर्च करवाने और वाषिकीत्सव में अनिवार्य शुल्क लेने जैसी शिकायतें भी सामने आते रहती है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने कहा कि इन सारे मांगो की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग ने कई बिंदुओं पर सहमति जताते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जिससे आने वाले समय में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा।

श्री यादव ने कहा है कि यदि जिला शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों के खिलाफ कायर्वाही में कोताही बरतेंगे, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने से पीछे नही हटेगा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने कहा कि स्कूलों में शिक्षिकाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे मामलों में निजी विद्यालयों में शिक्षिकाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। शिक्षिकाओं को ऐसी घटनाओं में न्याय दिलाने छत्तीसगढ़ बजरंग दल एक प्रकोष्ठ का गठन करेगी और शिक्षिकाओं को सम्मान और न्याय दिलाने हरसंभव मददकारी बनेगी।

युवा फेस्ट–2026 का हुआ भव्य समापन : दायरा बैंड के सुरों पर थिरका धमतरी

विकसित भारत के आधार स्तंभ हैं युवा : मंत्री टंकराम वर्मा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

धमतरी के पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित दो दिवसीय 'युवा फेस्ट–2026' का आज अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक माहौल में समापन हुआ। इस महाकुंभ ने न केवल युवाओं की प्रतिभा को एक सशक्त मंच प्रदान किया, बल्कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति और आधुनिक संगीत के अद्भुत संगम से पूरे शहर को ऊर्जा से सराबोर कर दिया।

इस अवसर पर प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। अपने ओजस्वी उद्बोधन में मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि युवा फेस्ट जैसे आयोजन न केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देते हैं, बल्कि उनमें नवाचार और आत्मविश्वास का संचार भी करते हैं। आज का युवा ही 'विकसित भारत–2047' का मुख्य आधार स्तंभ है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करें। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की युवा–कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए युवाओं से इनका लाभ उठाकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

जादू बस्तर ने बिखेरा संगीत का जादू

कार्यक्रम के अंतिम दिन 'दायरा बैंड' (जादू बस्तर) की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही। बैंड ने छत्तीसगढ़ी लोकधुनों और समकालीन फ्यूजन के ऐसे सुर छेड़े कि पूरा परिसर झूम उठा। लोक और आधुनिक संगीत के इस बेजोड़ मेल ने युवा पीढ़ी के साथ–साथ सभी आयु वर्ग के दशर्कों का मन मोह लिया।

कौशल और संवाद का मंच

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि फेस्ट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था, जहाँ वे स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और कला–संस्कृति के व्यावहारिक ज्ञान से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भविष्य में भी युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए ऐसे आयोजन निरंतर करता रहेगा। शिक्षा विभाग और महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ यह आयोजन जिले के युवाओं के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ।

प्रशासन की सराहना और प्रतिभाओं का सम्मान

मंत्री श्री वर्मा ने सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर रामू रोहरा ने भी युवाओं से अपनी रचनात्मकता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। समापन समारोह में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल और नवाचार से जुड़ी 23 विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पीजी कॉलेज ने इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रनिंग ट्रॉफी अपने नाम की।

खास खबर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने की सौजन्य मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लोकसभा सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शर्मा का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें शॉल एवं बस्तर आर्ट की आकर्षक प्रतिकृति भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उनके बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने हज यात्रियों को वितरित किया फर्स्ट एड किट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा

आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हज यात्रियों को फर्स्टएड किट सौंपकर उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि रायगढ़ से सांसद रहने के समय से लेकर आज तक लगातार हज यात्रियों के स्वागत का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश से कुल 815 हज यात्री यात्रा पर जा रहे हैं और पहली बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया तथा मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से देश एवं प्रदेश की सुख–समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए उनकी यात्रा की सफलता की कामना की।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों को यह पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए दुआ करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अब हज यात्रा के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और अधिक लोगों को यह अवसर मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हुआ है।

कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने भी संबोधित किया और हज यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कांवड़िया एवं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की सीईओ डॉ. खुशबू उस्मान समेत समाज के प्रबुद्धजन और प्रदेश भर से आए हज यात्री मौजूद थे।

बस्तर में अब हो रहे है तेजी से निर्माण कार्य

रायपुर। नक्सलमुक्त आबूझमाड़ क्षेत्र में अब निर्माण कार्य तेजी से किये जा रहें। क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, ओवरहेड टैंक, लघु सिंचाई योजना सहित अन्य अधोसंरचनाओं के कायी ने जोर पकड़ लिया है पिछले दिनों नक्सलमुक्त आबूझमाड़ में सीटीई की टीम ने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

टीम ने नारयणपुर के हरिमाकटीला, सड़क का निरीक्षण किया। टीम ने देखा कि निर्मित सड़कों मोटाई और चौड़ाई को सही मानक स्तर की है, इसी तरह ग्राम ओरछा ब्लाक में निर्मित शेड की निरीक्षण किया गया। जिले के ग्राम पालकी में निर्मित ओवरहेड टैंक की टीम ने निरीक्षण किया। इसी तरह से जल निर्माण संसाधन विभाग के अंतर्गत बैनूर रिजर्वायरके नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। टीम ने उपस्थित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी ली एवं अधिकारियों को जरूरी मार्गदर्शन भी दिया। नक्सलमुक्त बस्तर में अब विभिन्न निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने जांच एजेन्सीयों के दल आसानी से पहुंच रहे हैं। तकनीकी टीमों द्वारा निर्माण कार्यों को कराने स्थानिय अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, जिससे अब अबूझमाड़ में निर्माण कार्य तेजी से किए जाने लगे हैं।

खेलों में समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ तैयार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

श्रीनगर में खेल चिंतन शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर श्रीनगर के शेर–ए–कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्रारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजन में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार इस चिंतन शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ खेलों के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा।

श्री साव ने बताया कि आज शिविर के पहले दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ देश में खेलों को नई दिशा देने पर मंथन किया गया। यह पहल न केवल नीतियों को मजबूत करेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को आगे लाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एकजुट होकर कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के हर गांव और हर शहर से नए खिलाड़ी उभरें और देश–विदेश के खेल मंचों पर अपना परचम लहराएं, यह हमारा लक्ष्य है।

26 अप्रैल तक चलने वाला यह शिविर देश में खेलों के समग्र विकास, नीति सुधार, वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को खेल शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा लगातार दूसरे वर्ष इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। चिंतन शिविर के पहले दिन के प्रमुख सत्रों में मेडल स्ट्रेटजी – खेलो इंडिया पर गहन मंथन किया गया। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर खेल प्रशिक्षकों के पोटेंशियल को विकसित करने पर सर्वसम्मति बनी। साथ ही वर्ष 2048 तक भारत को ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के रोडमैप पर व्यापक चर्चा हुई। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के विस्तार एवं उसके प्रभावी उपयोग को खेल विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया। खेल मंत्रालय द्वारा इस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

द्वितीय सत्र खेलो भारत नीति –केंद्र एवं राज्य समन्वय को सुदृढ़ करना विषय पर आयोजित हुआ। इस सत्र में विभिन्न राज्यों के बेस्ट प्रेक्टिसेस को साझा किया गया। खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के प्रभावी उपयोग, प्रतिभा पहचान तथा खेल अकादमियों के मानकीकरण पर विशेष बल दिया गया। सत्र के दौरान विद्यालय स्तर पर खेलों को सशक्त बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने, खेल शिक्षकों की भर्ती एवं उन्हें उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने पर सहमति बनी। साथ ही खिलाड़ियों का समग्र डॉटा–बेस तैयार करने पर राज्यों एवं केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि प्रतिभाओं की सही पहचान सुनिश्चित हो सके।

इस सत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि खिलाड़ियों को केवल नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश के लिए पदक जीतने के लक्ष्य के साथ समर्पित होकर खेलना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अधिक अवसर, सम्मान एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि खिलाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था (मॉडल) विकसित की जाए, जिससे वे नौकरी प्राप्त करने के बाद भी खेल जारी रखें और अपने खेल करियर को बीच में न छोड़ें।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संस्कृति विकसित करने, जमीनी स्तर पर सुविधाओं के विस्तार तथा बच्चों को अधिक समय खेल गतिविधियों में देने पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही खेल अधोसंरचना के निर्माण में विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई।

तीसरे सत्र में डोपिंग एवं खेल नैतिकता पर गंभीर चर्चा हुई। खेलों में प्रतिबंधित दवाईयों के उपयोग पर कड़े नियम बनाने तथा डोपिंग को अपराध की श्रेणी में लाने के विषय पर केंद्र सरकार एवं खेल मंत्रालय की सख्त नीति को दोहराया गया। इस सत्र में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने खेलों में सुरक्षित एवं पेशेवर वातावरण सुनिश्चित करने तथा खिलाड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेफ गॉर्डिंग ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया।

ग्राम सभा में ग्रामवासियों को जनगणना के सम्बन्ध किया जा रहा है जागरुक, प्रथम चरण में मकानों की हुई गणना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 24 अप्रैल 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को आगामी जनगणना 2027 और स्व–गणना प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सही जानकारी भरने, मकान सूचीकरण, और जनगणना प्रगणकों को सहयोग देने के लिए प्रेरित करना है। ग्रामीणों को मोबाइल फोन के माध्यम से जनगणना पोर्टल पर स्वयं की जानकारी ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। तहसीलदार और ग्राम प्रभारी अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा में जनगणना पोर्टल का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे लोग सही जानकारी दर्ज कर सकें। जनगणना के सही आंकड़ों से भविष्य की विकास योजनाओं, संसाधन वितरण और प्रशासनिक निणर्यों को बेहतर बनाना है।

ग्राम पंचायत देवदा तहसील मंदिर हसौद में, ग्राम पंचायत नाहरडीह में पंचायती राज दिवस, ग्राम पंचायत निमोरा,ग्राम पंचायत खमतराई तहसील आरंग में आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को जनगणना से संबंधित सभी आवश्यक बिंदुओं की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान सहजता से किया गया है। ग्राम सभा के दौरान जनगणना की प्रक्रिया, इसकी गोपनीयता, तथा सही जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है। जनगणना में दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रहती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बैठक में सरपंच उप–सरपंच, पंचायत सचिव सहित जनप्रतिनिधिगण और ग्राम वासी उपस्थित रहे।

भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में 01 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि मे संचालित किया जाएगा। यह चरण जनगणना प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके माध्यम से प्रत्येक आवासीय एवं गैर–आवासीय भवन, मकान की स्थिति, उपयोग एवं उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी।

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इस बार आम जनता की सुविधा के लिए स्व–गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक नागरिक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के मध्य निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपने परिवार एवं मकान से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। स्व–गणना करने वाले परिवारों को एक स्व–गणना आईडी प्रदान की जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा प्रगणक के आने पर प्रगणकों को देना होगा। इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित की जाएगी– प्रत्येक भवन एवं मकान की संख्या, स्थिति एवं प्रकार, मकान का उपयोग, (आवासीय/व्यावसायिक/अन्य), निर्माण की प्रकृति (कच्चा/पक्का/अर्ध–पक्का), परिवारों की संख्या एवं उनके आवासीय विवरण, उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं, जैसे– पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रसोई गैस/ईंधन का प्रकार, इंटरनेट/संचार सुविधाएं यह जानकारी देश की सामाजिक–आर्थिक योजनाओं, शहरी एवं ग्रामीण विकास, आवास योजनाओं, जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों तथा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रगणक निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक घर पर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। प्रगणक अधिकृत पहचान पत्र के साथ जाएंगे, जिसकी पुष्टि नागरिकों द्वारा की जा सकती है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रगणको को सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। स्व–गणना कर चुके परिवारों को अपनी प्रगणक को बतानी होगी। जनगणना देश की सबसे व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो सरकार को जनसंख्या, आवास एवं बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने में सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जापान के प्रतिनिधिमंडल से की सौजन्य मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर अपने जापान प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की उद्योगोन्मुखी और निवेश प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापान तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश है और वहां की उन्नत विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के निवेश और सहयोग से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार हुआ है, जिससे उद्योगों के विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में अपने निवेश को और बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, एफसेनल के डायरेक्टर युकीहिरो मोमोसे, कोनोइके ट्रांसपोर्ट के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर तोशीहीरो फूजीवारा, एफएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार दीक्षित तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी के. डी. दीवान उपस्थित थे।

संपादकीय

सचिन खेल को बढ़ावा देने बस्तर आए,यही बड़ी बात है

देश के महान क्रिकेट खिलाडी.सचिन छत्तीसगढ़ तो कई बार क्रिकेट खेलने आए हैं। इस बार वह छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र बस्तर आए है सचिन जैसे महान खिलाड़ी के लिए बस्तर के बच्चों के लिए समय निकालकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आना ही अपने आप में बड़ी बात है। देश में कई खेलों के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वह अपने राज्य में अपने क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने का काम करते होंगे।सचिन भी चाहते तो अपने राज्य महाराष्ट्र तक ही सीमित रहकर वहां के बच्चों में खेल को बढ़ावा देने का काम कर सकते थे।क्रिकेट अकादमी खोलकर बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दे सकते थे और पैसा कमा सकते थे लेकिन उन्होंने बस्तर को चुना खेल को बढ़ावा देने के लिए। उनकी यही सोच उनको बाकी बड़े खिलाड़ियों से अलग करती है।आजकर बड़े खिलाड़ी तो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पैसों का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं .जिस देश के लोगों ने उनको पैसा दिया है, वह देश के बच्चों के लिए उस पैसे का एक हिस्सा खर्च नहीं करना चाहते हैं। सचिन ने पैसा कमाया है तो वह कमाए पैसों का सदुपयोग भी कर रहे हैं।

पीएम मोदी जब भी देश के किसी प्रतियोगिता में विजयी खिलााड़ियों से मिलते हैं तो चाहे वह ओलिंपिक विजेता को,विश्वकप विजेता है, महिला हों या पुरुष खिलाड़ी है पैरा खिलाडी.हो उनसे यह जरूर कहते हैं कि आप अपने शहर के तीन स्कूल में जरूर जाना, शहर के बच्चों के बीच जरूर जाना।इससे बच्चों को खेलने की प्रेरणा मिलती है।सचिन तो इस मामले में सभी खिलाड़ियों से ज्यादा लोकप्रिय है और वह जैसा जीवन जीते हैं, उससे उनको देश का सबसे आदर्श खिलाड़ी माना जा सकता है। वह आज जब बस्तर आए तो ऐसा लगा कि महान लोगों की सोच में कितनी समानता होती है, पीएम मोदी चाहते है कि महान खिलाड़ियों को बच्चों को बीच जाना चाहिए और महान खिलाड़ी सचिन बस्तर के बच्चों के बीच आते हैं तो बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलना स्वाभाविक है। देश के महान खिलाड़ी से देश के बच्चों को महान खिलाडी.बनने की प्रेरणा मिलती है। ।देश मे एक महान खिलाड़ी होने पर कई महान खिलाड़ी पैदा होने की पूरी संभावना होती है।

सचिन ने इस देश में क्रिकेट का सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया है। आज देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी हैं तो उनमें ज्यादातर ने सचिन को ही क्रिक्रेट खेलते देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज देश में विराट कोहली,युवराज,रोहित शर्मा,धोनी आदि दूसरी पीढ़ी के खिलाड़ियों के बाद आज देश में क्रिकेट में क्रिकेट की तीसरी व चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है।बड़े खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर ही खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना देखता है और कपिल,गावस्कर को देखकर सचिन सचिन बनता है तो सचिन को देखकर विराट कोहली, युवराज आदि बनते हैं।विराट कोहली के बाद अभिषेक,वैभव बडा खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं। किसी देश में एक महान खिलाड़ी पैदा होता है तो उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर कई महान खिलाड़ी पैदा होते हैं।

सचिन ने बचपन में मुंबई की गलियों मे क्रिकेट खेलकर महान खिलाड़ी बने है वह जानते हैं कि बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तो खेल की सुविधाओं की बहुत कमी होगी लेकिन खेल प्रतिभा बहुत होगी। यही वजह है कि वह बस्तर आकर कहते हैं कि खेल के प्रति जुनून के साथ ही खेल सुविधाओं का होना जरूरी है कम से में कम न्यूनतम सुविधाएं तो होनी चाहिए। आदि एक अच्छा मैदान खेलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है।यही वजह है सचिन का जोर शुरुआत में बस्तर में खिलाड़ियों को कुछ अच्छे मैदान उपलब्ध कराना है।वह ऐसा कर रहे तो माना जा सकता है कि वह ऐसा करने में जरूर सफल होंगे।

मैदान के बाद खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है तो सचिन के फाउंडेशन का प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को ही खेल का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षक बनाया जाए।सचिन ने इस साल शुरुआत की है। आने वाले समय में बस्तर में खेलों का विकास होगा और अच्छे खिलाड़ी बस्तर से निकलकर देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। सरकार भी अपने स्तर पर बस्तर व सरगुजा ओलिंपिक का आयोजन कर राज्य के आदिवासी युवाओं को खेल मंच मुहैया करा रही है।इससे आदिवासी क्षेत्र की प्रतिभाओं का अपने प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है।इस काम में सचिन के शामिल होने से यह काम और अच्छे से हो सकेगा और वह बस्तर जो कभी नक्सलियों आतंक के लिए बदनाम था आने वाले समय में अपने खिलाड़ियों के खेल के कारण जाना जाएगा ।सचिन ने कहा है कि बस्तर में हीरे है उनको तराशने की जरूरत है तो यह हीरे एक दिन जरूर अपनी चमक से दुनिया को हैरान करेंगे।

मुक्त प्रवाह में खलल के बीच मछुआरे की सुध

पश्चिम वैश्विक प्रवाह में व्यवधान की असल कीमत व्यवस्था एवं ज़िंदगियां चुका रही हैं। होर्मुज में नाकाबंदी का असर आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के चलते ऊर्जा (पैट्रोल) व खाद्यान्न की कीमतों पर हो रहा है। जिसका असर महंगाई के रूप में आमजन के जीवन पर ही पड़ेगा। एक ऐसी साझी वैश्विक स्वचालित रूपरेखा की जरूरत है जिसके आवाजाही का सतत बने रहना जरूरी है। वैश्विक प्रवाह यानी मुक्त आवाजाही में व्यवधान पड़ता है, तो इसका असर नाकाबंदी वाले बिंदु या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। दूर तक फैलता है। तेल से लेकर भोजन और रोजी-रोटी तक, इसकी कीमत व्यवधान वाली जगह से सुदूर क्षेत्रों को भी सहनी पड़ती है। जिस आवाजाही का सतत बने रहना जरूरी है उसके लिए हर बार वार्ता करने की जरूरत क्यों पड़े। यह सततता नियमबद्ध हो न कि अपवादवश पुनः खोलना।

जब ह्यप्रवाह के नियमह्ल की व्याख्या पहली बार द ट्रिब्यून में की गई, तो यह विचार बतौर सिद्धांत नहीं आया था। यह एक गैर-रूढ़िवादी किंतु सहजबोध से उत्पन्न धारणा थी, क्योंकि मछुआरा हर जगह मौजूद है, हर क्षेत्र में जहां जीवन-निर्वाह मुक्त आवाजाही पर निर्भर है। जहां सततता रही वहां स्थिरता कायम है, जहां इसमें बाधा बनी, व्यवस्था पर दबाव पड़ा। जब मुक्त प्रवाह में खलल पड़े तो ताकतवर में तकरार होता है, वहां भुगतना कमजोरों को पड़ता है। कीमत मछुआरे को चुकानी पड़ती है। फिर, होर्मुज स्ट्रेट में, दुनिया ने उस कोताही की कीमत भुगती, जब आवाजाही नियमों की रूपरेखा तय करने से मुंह चुराया। व्यवधान पुनः बना, त्वरित परिणाम भी। बाजार में वस्तुओं की कमी हो गई। बीमा कंपनियां हिचकिचाने लगीं। आपूर्ति शृंखला लड़खड़ा गई। कुछ ही दिनों में, राष्ट्र जुटे, संधि या गठबंधन के तहत नहीं, बल्कि निर्भरता वश। यूके-फ्रांस की अगुवाई में एक प्रयास होने लगा, बतौर एक युद्धकालीन गठबंधन नहीं बल्कि जल परिवहन सुचारू रखने हेतु सुरक्षात्मक प्रबंधन के रूप में। सुरक्षा प्रदाता पोत साथ भेजने की बात चली। अपने नौसैन्य जहाज और सैनिक तैनात करने की पेशकश हुई। उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि जल मार्गों में मुक्त आवाजाही बनी रहे।

होर्मुज गठजोड़ कोई गठबंधन नहीं। स्वीकारोक्ति है। प्रवाह के नियम सीएलओसीस (सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन) का विकल्प नहीं। खंडित दुनिया में, जो मार्ग मुक्त रहना चाहिए हर बार खतरा आने पर उसको खुलवाने को समझौता वार्ता की नौबत क्यों बने? आवाजाही खुद अक्षुण्ण रहे। लेकिन उस दिन कुछ और हुआ। इस्लामाबाद में इस मुद्दे पर एक बैठक हुई थी। दोनों पक्ष वार्ता मेज पर आए। अपनी-अपनी स्थिति बताई व अड़े रहे। लेकिन कोई हल नहीं निकला। दुनिया ने वार्ता होते देखी पर उससे नई संरचना जन्म लेते नहीं। मौके को मिसाल में बदलना हाथ से निकल गया। यह सही होने की बात नहीं है। बल्कि इस बारे कि सही होने से क्या पता चलता है और क्या दायित्व उत्पन्न होते हैं। वही कुछ इस पल का अनुग्रह है। जो हुआ वह नियमों की रूपरेखा बनना नहीं था। यह दबाव में आकर बनाई एक कामचलाऊ व्यवस्था थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने इक्यावन देशों को इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि सिद्धांत ने यह करवाया बल्कि इसलिए कि कोताही की फौरी कीमत चुकानी पड़ रही है और नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। वे संरक्षक जरूरत के चलते बने हैं। यह फर्क मायने रखता है। इस दिशा में प्रवाह का नियम सही साबित हुआ। लेकिन सिद्धांत और संरचना के बीच अंतर खतरनाक रूप से कायम है।

इंसान जो कीमत चुका रहा : इससे पहले कि हम जलडमरूओं और शीर्ष समझौता वार्ताओं पर फिर आएं, उनके बारे में सोचें कि जिन्हें व्यवधान की कीमत चुकानी पड़ती है। न रणनीतिकारों को, न मंत्रियों को, तेल के व्यापारियों को भी नहीं, यह तो केरल के किसी मछुआरे को सहनी पड़ रही है, जिसके लिए डीजल का दाम दोगुना हो गया। साहेल का वह किसान जिसकी खाद नहीं पहुंची। वियतनाम का कोई कारखाना मालिक जिसका निर्यात आर्डर जहाजरानी रूट बदल जाने पर खारिज हो गया। काहिरा का परिवार जो गेहूं की आवक में कमी से रोटी के बढ़े दाम देने पड़ रहे।

यह दुनिया में बार-बार दस्तक देने वाली सच्चाई है, जो प्रवाह सुचारु रहने पर निर्भर है, क्योंकि इसको सुरक्षित रखने के वास्ते नियमों की रूपरेखा नहीं बनाई गई। कोविड-19 को किसी पासपोर्ट की दरकार नहीं थी। यह उन्हीं राहों से फैला जिनसे सामान, पूंजी और लोग आवाजाही करते हैं। जब प्रवाह रुका, तो सबसे कम बचत वालों को सबसे पहले और ज़्यादा भुगतना पड़ा यानि दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक। व्यवधान उनका बनाया नहीं था। फिर भी भुगतना उन्हें ही पड़ा।

युद्ध का असर अब वहीं तक सीमित नहीं रहता जहां यह चल रहा होता है। यह आपूर्ति शृंखला में दाखिल हो जाता है। एक इलाके की जंग दूसरे इलाके के अन्न भंडार खाली करवा देती है। एक बंदरगाह पर हुए हमले से समूचे महासागरीय क्षेत्र में दाम बढ़ जाते हैं। आज युद्ध एक योजनाबद्ध व्यवधान है।

नाकेबंदी अपना फायदे खुलेआम घोषित नहीं करती। होर्मुज जलडमरू बंद होने के कुछ हफ्तों में ही, तेल का दाम बढ़कर सौ डॉलर प्रति बैरल होने का बोझ हरेक पैट्रोल पंप, हर ट्रांसपोर्ट लाइन, ढुलाई की जाने वाली हर चीज की कीमत पर पड़ा। केरल के मछुआरे ने इसके लिए वोट नहीं दिया था, फिर भी इसकी कीमत चुका रहा है। कोविड-जलवायु परिवर्तन-युद्ध-नाकाबंदी, इसका उदगम स्थल भिन्न, प्रभाव इनका एक जैसा। शुरुआत कुछ लोगों के फैसलों से होती है और हश्र करोड़ों-अरबों लोगों को प्रभावित करता है। हरेक की शुरुआत खबरों की सुर्खियों के रूप में होती है और परिणति घर खर्च पर पड़े बोझ के रूप में। हरेक रणनीति कमरे से शुरू होकर रसोई, खेत और कारखानों पर मार करती है। आम आदमी होर्मुज जलडमरू में नहीं रहता। वह यहां से निकलने वाले जलमार्ग के किसी छोर पर रहता है, उन कमरों में बैठकर लिए फैसलों के छोर पर जिनमें घुसने की उसे इजाजत नहीं, वह जिस व्यवस्था पर निर्भर है उसपर उसका वश नहीं। इसी वजह से प्रवाह का नियम रणनीतिक अंतर्दृष्टि बनकर नहीं रह सकता। इसमें सामाजिक सरोकार होना जरूरी है। जब प्रवाह में व्यवधान पड़ता है तो पहला नुकसान हमेशा उन लोगों का होता है, झटका झेलने की जिनकी सामर्थ्य सबसे कम होती है। होर्मुज प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तेल की एक कीमत होती है। टैंकर ट्रैक किये जा सकते हैं। व्यवधान अपनी घोषणा खुद करता है। अगला संकट शायद न करे। एक कटा हुआ डेटा केबल किसी काम का नहीं। सेमीकंडक्टर की कमी चुपचाप बढ़ती है। एक खाद्यान्न मार्ग धीरे-धीरे बंद होता जाता है जबतक कि फिर से न खुले। होर्मुज के लिए 51 देश समय रहते एकजुट हुए। हो सकता है अगली बार, नाकाबंदी का बिंदु शायद इंतजार न करे।

जब प्रवाह फिर से रुक जाए: सिद्धांत और व्यवधान तले एक सरल सच दबा होता है। प्रत्येक व्यवस्था जो हमने बनाई है, संयुक्त राष्ट्र, लॉ ऑफ द सी, जलवायु संधि, व्यापार तंत्र, सब इस एक साझी धारणा पर टिके हैं: कि निरंतरता में इंसानियत का साझा हिस्सा है। इस धारणा को अनेक नाम दे रखे हैं। बहुआयामी व्यवस्था,नियमाधारित तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि। लेकिन इसका सबसे पुराना और ईमानदार नाम बस यही है: वैश्विक साझेदारी। फिर भी हम बर्ताव करते हैं मानो व्यवस्था को टुकड़ों में बांटकर सुरक्षित रख सकते हैं। हम अलग-अलग हिस्सों में समझौता करते हैं जबकि व्यवधान आसानी से उनके बीच विचरता है। संप्रभुता की भाषा सीमित रहती है। ज़िंदा रहने की सच्चाई अब सीमित नहीं रही। युद्ध दर्शाता है कि अस्थिरता विस्तार लेती है। होर्मुज हमें याद दिलाता है कि जिस जलडमरू को शायद हम कभी न देख पाएं, वह उस रोटी की कीमत तय कर रहा है, जो हमें बारम्बार खरीदनी पड़ती है। प्रवाह का सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत नहीं। यह एक-दूसरे पर निर्भरता स्वीकार करना है। निरंतरता के संरक्षक शक्ति के प्रहरी न होकर जन सेवक हैं। अब जबकि ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज को निरापद करने के लिए दुनिया को लामबंद कर रहे हैं, बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। व्यवधान के बोल निरंतरता की आवश्यकता को राह दे रहे हैं। जो कभी जबरदस्ती नियंत्रित था वह अब निर्भरता की मजबूरी है। फिर भी, जब अन्य राष्ट्र संकट की घड़ी में गठबंधन बना रहे हैं, हमारी भौगोलिकता और सभ्यता के गुण एक बड़ी भूमिका की ओर इशारा करते हैं, महज किश्तवार प्रतिक्रिया देने वाले न बनकर, हम एक भागीदार के रूप में, बल्कि अधिक टिकाऊ सिद्धांत के संभावित रचयिता के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

सुविधा को स्वच्छंदता बनने से रोकने की पहल

डॉ. सुधीर कुमार

इस डिजिटल खेल का सबसे भयावह पहलू नशीली दवाओं और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध दुरुपयोग है। अनिद्रा या तनाव से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के मंगवाई गई नींद की गोलियां न केवल घातक लत पैदा करती हैं, बल्कि विशेषज्ञ की निगरानी के अभाव में मानसिक संतुलन को भी पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं।

बदलते दौर ने दवाओं की उपलब्धता को जरूरत से सुविधा में बदल दिया है। सामाजिक भरोसा अब स्माटफीन की एक क्लिक में सिमट गया है। डिजिटल इंडिया की इस सुनहरी तस्वीर में दवाएं महज आधे घंटे में आपके दरवाजे पर पहुंच रही हैं। लेकिन कानून की कसौटी पर सवाल यह है कि क्या दवाओं की होम-डिलीवरी को पिज्जा ऑर्डर करने जितना ही सरल मान लेना चाहिए? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की जटिल कड़ियां और शेड्यूल-एच दवाओं के जोखिम संकेत देते हैं कि ई-फार्मेसी की यह डगर जितनी चिकनी दिखती है, कानूनी और चिकित्सकीय सुरक्षा के लिहाज से उतनी ही पथरीली है।

ई-फार्मेसी कंपनियों का तर्क है कि वे तकनीक के जरिए दवाओं की उपलब्धता आसान बना रही हैं। वहीं, केमिस्ट का कहना है कि यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। असली संकट तब शुरू होता है जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी वैध पर्चे के या पुराने, धुंधले पर्चों के आधार पर दवाएं बेची जाने लगती हैं। एक आम आदमी के लिए यह केवल सुविधा है, लेकिन कानून की किताब में यह अपराध की श्रेणी में आता है। जब आप बिना डॉक्टर की सलाह के खुद अपना डॉक्टर बनकर दवाएं मंगवाते हैं, तो आप अनजाने में एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहे होते हैं, जहां से निकलना मुश्किल है।

भारत में औषधियों का व्यापार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अधीन है। चूंकि यह कानून इंटरनेट युग से पूर्व का है, इसलिए ई-फार्मेसी फिलहाल एक ग्रे एरिया में सक्रिय हैं। कानून की स्पष्ट मर्यादा है कि शेड्यूल एच और एच-1 श्रेणी की दवाएं बिना पंजीकृत डॉक्टर के वैध पर्चे के नहीं बेची जा सकतीं; ऐसा करना सीधे तौर पर विधिक उल्लंघन है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के पास पंजीकरण अनिवार्य होगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा को तकनीक के माध्यम से सुदृढ़ करना है।

इस डिजिटल खेल का सबसे भयावह पहलू नशीली दवाओं और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध दुरुपयोग है। अनिद्रा या तनाव से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के मंगवाई गई नींद की गोलियां न केवल घातक लत पैदा करती हैं, बल्कि विशेषज्ञ की निगरानी के अभाव में मानसिक संतुलन को भी पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रतिबंधित दवाओं का अवैध व्यापार आपको गंभीर कानूनी पचड़ों और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। वहीं, बिना पर्चे के एंटीबायोटिक्स का सेवन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जन्म दे रहा है, जिससे भविष्य में सामान्य संक्रमणों पर भी दवाएं बेअसर हो जाएंगी। पारंपरिक स्टोर एक मानवीय स्पर्श और तत्काल जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं, जहां फार्मासिस्ट पर्चे की भौतिक जांच कर उसके दुरुपयोग को रोकता है और मरीज को दवाओं के साइड इफेक्ट्स के प्रति सचेत कर एक व्यक्तिगत विश्वास की कड़ी बनाता है।

इसके विपरीत, ई-फार्मेसी की दुनिया एल्गोरिदम पर टिकी है, जहां सुविधा के साथ जोखिम भी गहरे हैं। यहां सबसे बड़ी चिंता कोल्ड चेन मेंटेनेंस (दवाओं के रखरखाव का तापमान) को लेकर है। यदि इंसुलिन जैसी जीवन-रक्षक दवाएं गोदाम से ग्राहक तक पहुंचने के दौरान निर्धारित तापमान पर न रखी जाएं, तो वे बेअसर होकर जानलेवा साबित हो सकती हैं। सुरक्षा की पहली शर्त यह है कि उपभोक्ता केवल उन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें जो सरकार द्वारा पंजीकृत हों। विधिक दृष्टिकोण से, 6 महीने से अधिक पुराने पर्चे पर दवा मंगवाना न केवल स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है, बल्कि इसे अवैध खरीद की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। भारी डिस्काउंट के प्रलोभन में गुणवत्ता से समझौता करना अपने जीवन को दांव पर लगाने जैसा है।

अक्सर ई-फार्मेसी कंपनियां खुद को महज बिचौलिया बताकर पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने अब आम जन को एक सशक्त विधिक हथियार दिया है। यदि कोई कंपनी गलत या घटिया दवा की आपूर्ति करती है, तो उसे डेफिशिएंसी इन सर्विस (सेवा में कमी) के आधार पर उपभोक्ता अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्षति की स्थिति में हर्जाना भरने व कानूनी कारर्वाई का सामना करने के लिए बाध्य हैं। डिजिटल बिल और पैकेजिंग को साक्ष्य के रूप में संभाल कर रखना इस कानूनी लड़ाई में आपका सबसे बड़ा आधार है। उआवश्यकता ई-फार्मेसी को प्रतिबंधित करने की नहीं, बल्कि सुविधा को स्वच्छंदता बनने से रोकने की है।

कच्ची पर्ची पर रोक से किसानों को राहत की पहल

डॉ. विरेन्द्र लतिहार

हरियाणा की कृषि मंडियों में अनेक आढ़ती तय नियमों का उल्लंघन कर किसानों को अत्यधिक ब्याज पर कर्ज देते रहे व बीज-उर्वरक-कृषि रसायन आदि बेचते रहे हैं। इस संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर अमल के बाद इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कृषि निवेश व्यापार पर प्रतिबंध लगा है। जिससे वर्षों से जारी किसानों के साथ अन्याय पर रोक लगेगी।

कृषि लागत और मूल्य आयोग और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में अधिकांश समय, फसल उपज की कीमतें औसतन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर और समर्थन मूल्य से नीचे बनी रहीं और बिचौलिए आढ़तियों द्वारा शोषण के कारण कृषि उपज वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ता मूल्य में किसानों का हिस्सा बेहद कम बना हुआ है। यह हिस्सा फसल और बाजार के आधार पर 28 से 78 प्रतिशत के बीच है। ये चिंताजनक आंकड़े मंडी व्यवस्था में मूलभूत नीतिगत सुधारों की आवश्यकता दर्शाते हैं।

हरियाणा की कृषि उपज मंडियों में बिचौलिए आढ़तियों के शोषण से किसानों को मुक्त करने के लिए, लागू किए गए फसल बिक्री पर धनराशि किसान के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित करने जैसे नीतिगत सुधारों के सकारात्मक नतीजे मिले हैं। फसल बिक्री से किसानों को मिलने वाली राशि पर आढ़तियों की पकड़ ढीली हुई है।

आढ़तियों की कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। जिसके चलते 1 अप्रैल 2026 को प्रदेश की मंडियों के आढ़तियों को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था तुरंत बन्द करने और उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद कानूनी रसीद जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने के आदेश जारी किए। कृषि विशेषज्ञ के अनुसार, अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगने से, प्रदेश के किसानों को 30-40 प्रतिशत यानि गेहूं-धान फसल चक्र में 25-30 हजार रुपये प्रति एकड़ ज्यादा सालाना लाभ होगा। इस फैसले को किसान हित में महत्वपूर्ण कृषि विपणन सुधार माना जा रहा है।

हरियाणा की मंडियों में लगभग 16 करोड़ क्विंटल खाद्यान्न, 1.5 करोड़ क्विंटल तिलहन, एक करोड़ क्विंटल दलहन और 12-15 लाख बेल कपास आदि फसल उपज का वार्षिक विपणन होता है । इन सबका मौजूदा समर्थन मूल्य लगभग 70,000 करोड़ रुपये वार्षिक है। गौरतलब है कि मार्च-2022 से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में 114 मुख्य मंडियों और कुल 376 उप-मंडियों/खरीद केन्द्रों का विशाल नेटवर्क है, जिसमें लगभग 40 हजार आढ़ती कार्यरत हैं। इन्हें विभिन्न फसलों की बिक्री पर 2 से 2.5 प्रतिशत कमीशन (आढ़त) मिलता है। जो लगभग 1400 करोड़ रुपये वार्षिक बनता है। ऐसे में प्रत्येक आढ़ती को औसत 3-4 लाख रुपये वार्षिक आढ़त बनती है। जो प्रदेश में कुशल श्रमिक के वार्षिक वेतन से भी कम है।

निस्संदेह, प्रदेश की कृषि मंडियों में आढ़तियों की संख्या जरूरत से ज्यादा होने के कारण, वैध आढ़त का धंधा लाभप्रद नहीं रहा। ऐसे में कुछ आढ़तियों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कच्ची पर्ची व्यवस्था, मनी लॉन्ड्रिंग व नकली बीज-खाद-दवाई बेचने जैसे अवैध धन्धे अपना लिये। वहीं तन्त्र के कुछ भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत से किसानों का शोषण और सरकारी धन का गबन करते रहे हैं। आढ़तियों ने कृषि उपज विपणन कमेटी एक्ट-1961 रूल्स-1962 का उल्लंघन कर कच्ची पर्ची सिस्टम से वर्ष-2025 में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के धान घोटाले में सरकारी धन के गबन को अंजाम दिया। जिसकी राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर जांच कर रही है। जबकि किसान संगठन और राजनीतिक दलों के नेता आढ़तियों द्वारा किये गये कथित घोटाले की विस्तृत जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग कर रहे हैं। कथित तौर पर यह सरकारी धन आढ़तियों के जरिये काले धन में प्रवर्तित किया गया।

हरियाणा राज्य कृषि उपज विपणन कमेटी अधिनियम के तहत राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड मंडियों में कृषि उपज की खरीद-फरोख्त करने के लिए कमीशन एजेंट को आढ़त का लाइसेंस देता है जो सरकार के दिशानिर्देश अनुसार व्यापार करने को कानूनी तौर पर बाध्य हैं। लेकिन बिचौलिए आढ़ती मिलीभगत से तय नियमों का उल्लंघन करके मनी लॉन्ड्रिंग धंधे (किसानों को अत्यधिक ब्याज पर कर्ज देना आदि) में लगे हुए हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए इन अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति जब्त करने और इनमें शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, मजबूर कजर्मंद किसानों को आढ़ती बिना लाइसेंस लिए ही कथित नकली बीज-उर्वरक- कृषि रसायन आदि बेचकर, किसान और खेती को गंभीर नुकसान कर रहे हैं। आढ़तियों की अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और कृषि निवेश व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने से हरियाणा की मंडियों में वर्षों से हो रहे करीब दस हजार करोड़ रुपए वार्षिक के किसानों के शोषण और सरकारी धन के गबन पर भी लगाम लग सकेगी और खेती टिकाऊ बनेगी। जिससे कृषि विपणन में क्रान्तिकारी सुधार और लेन-देन में पारदशिर्ता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आढ़तियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग व धोखाधड़ी पर नकेल कसेगी।

मोहिनी एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

हिन्दू पंचाग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णुजी की उपासना करनी चाहिए।

मोहिनी एकादशी का महत्व

भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज ! त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णुलोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णुजी के मोहिनी स्वरुप का पूजन-अर्चन किया जाता है।

मोहिनी एकादशी की पूजाविधि

एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरुप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चन्दन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप-दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल-कपट,लालच,द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर,श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्तिभाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें।

इसलिए लिया भगवान ने मोहिनी रूप शास्त्रों के अनुसार मोहिनी, भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला, तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार, सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया।यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्रीराम ने रखा था।

पापियों की संगत, गंभीर पाप से मुक्ति दिलाता है मोहिनी एकादशी व्रत

वैशाख माह की मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 को है. मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है. इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त हो कर लक्ष्मी-नारायण की भक्ति कर पाता है. शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है. आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत में कथा क्यों की जाती है, क्या है इसकी महिमा.

हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरुर किया जाता है. दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है. महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं. वहीं कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है. चूंकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा पाठ जरुर करना चाहिए, इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है.

महाभारत में कथा का वर्णन

एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है. भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था. चूंकि ये व्रत सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है, इसीलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. वैशाख के महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है. एकादशी व्रत को रखने वालों को नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए. मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है.

मोहिनी एकादशी व्रत कथा

प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था. उसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन-धान्य से पूर्ण था. उसका नाम धनपाल था. वह अत्यन्त धर्मात्मा और नारायण-भक्त था. वैश्य के पाँच पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यन्त पापी व दुष्ट था, वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था.

बुरी संगत में पापी बना बेटा

मद्यपान, जुआ आदि बुरे कर्मों में उसने अपने पिता का बहुत धन बर्बाद किया. जब काफी समझाने पर भी वह नहीं सुधरा तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया. वह अपने गहने और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा. धन खत्म हो जाने पर उसके दुष्ट साथी भी साथ छोड़कर चले गए. इसके बाद वह चोरी कर अपनी भूख को शांत करने लगा लेकिन एक दिन पकड़ा गया, हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया. इसके बाद भी जब उसने चोरी करना नहीं छोड़ा तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया.

झेलना पड़े तमाम कष्ट

कारावास में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा, अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश मानना पड़ा. इसके बाद जानवरों को मारकर पेट भरने लगा. एक दिन भोजन की तलाश में वह कौटिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने ऋषि से अपनी पीड़ा बताई. पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा. उसने विधि अनुसार ये व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गये और अन्त में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णुलोक को गया.

क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपना उचित है?

आजकल संतों की नहीं, कथा वाचकों की लोग सुनने लगे हैं। कथाओं को कहने का तरीका भी बदल गया है। वर्तमान में एक कथावाचक बहुत प्रसिद्ध हो चले हैं, जिनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। वे कहते हैं कि शिवजी का पंचाक्षरी मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं है- इसका जप करना चाहिए। इसे वे महामृत्युंजय मंत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली बताते हैं। क्या अब हम ऊँ नमः शिवाय को जपना छोड़ दें?

ऊँ नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं

श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का अर्थ - श्री शिव मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं।

ऊँ नमः शिवाय का अर्थ - ओंकार या ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार।

कहते हैं कि ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ऊँ या ओम के बगैर मंत्र अधूरा माना जाता है। नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र है जिसके आगे ओम लगाने से उसकी पूर्णता होती है और शिवजी के साथ ही निराकार ब्रह्म (ईश्वर) भी जुड़ जाता है। शिवजी का एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में निराकार भी है। अतः नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मन्त्र में प्रणव यानी ऊँ लगाकर इसका जप करना ही उचित है।

तस्य वाचकः प्रणवः।।- तैत्तिरीयोपनिषद् 1.27॥ अर्थात उसका वाचक (नाम, इंगित करने वाला) प्रणव है। अस्य ओम नमः शिवाय पञ्चाक्षर मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिवो देवता। अर्थात इस शिव पंचाक्षरमन्त्र के वामदेव ऋषि हैं, अनुष्टुप् छन्द है, सदाशिव देवता हैं)

जहां तक सवाल पंचाक्षरी मंत्र का है तो वह नमः शिवाय ही है जिसमें? लगाकर उसका जप किए जाने का ही उचित तरीका है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। हालांकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप भी किया जा सकता है क्योंकि भगवान को किसी भी तरीके या रूप में भजें वह आपके ही हैं। उल्लेखनीय है कि श्री शब्द माता लक्ष्मी का नाम है। शिवजी के नाम के आगे इसका उपयोग नहीं होता है।

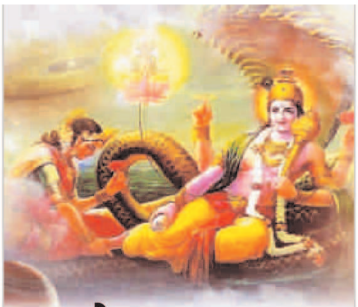

वैशाख शुक्ल एकादशी पर करें श्रीहरि की पूजा

वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं. इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल के दिन रखा जाएगा. उस दिन द्विपुष्कर योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं. विष्णु पूजा के समय सर्वार्थ सिद्धि योग बना होगा, जो आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए अच्छा योग माना जाता है. मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो श्रीहरि की पूजा कर सकते हैं. श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉ मृत्युञ्जय तिवारी बता रहे हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में.

मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा

एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है? इस व्रत का महत्व क्या है? इस बारे में आप विस्तार से बताएं. इस पर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं. महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो इसकी कथा बताई थी, वह कथा आपको भी बताते हैं.

मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं. वह मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है. इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है- भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान शासन करता था. उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धर्मात्मा था. वह भगवान विष्णु का परम भक्त था. उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया था, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे. उसके पांच बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि था. धृष्टबुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था. वह पाप कर्मों में लिप्त रहता था. उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया. बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया. उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा. एक बार उसे पकड़ लिया गया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया. दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया. बाद उसे नगर से ही बाहर निकाल दिया गया.

एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर घूमते-घूमते कौडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया. वह वैशाख का महीना था. ऋषि गंगा स्नान करके आए थे, उनके गीले वस्त्रों के छीटें उस पर पड़े. धृष्टबुद्धि को कुछ बुद्धि आई. उसने ऋषि कौडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं. इससे मुक्ति का मार्ग बताएं.

ऋषि कौडिन्य को धृष्टबुद्धि पर दया आ गई. उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है. इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे. उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई. मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया. व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया. जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया. मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है. जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गोदान के समान पुण्य लाभ होता है.

पुराणों में छिपा है केदारनाथ और बद्रीनाथ का इतिहास और भविष्य

केदारनाथ और बद्रीनाथ में खूब विकास किया जा रहा है जबकि केदारनाथ की बाढ़ ने एक झटके में सारे विकास कार्य ध्वस्त कर दिए थे। क्या आने वाले समय में भी यही होने वाला है? पुराणों में छिपा है केदारनाथ और बद्रीनाथ का इतिहास और भविष्य। बद्रीनाथ चार बड़े धामों में से एक है। आओ जानते हैं दोनों ही तीर्थ स्थलों का इतिहास और भविष्य।

- बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान था। लेकिन जब विष्णु जी ने यह स्थान देखा तो इसे देखकर वे मंत्रमुग्ध जैसे हो गए और उन्होंने तब इस स्थान को अपना बनाने के लिए यहां पर बालरूप की लीला की और शिव एवं पार्वती जी से यह स्थान ले लिया।
- वर्तमान बद्रीनाथ के पहले आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल हुआ करता था। इसे सबसे प्राचीन स्थान कहा जाता है जो उत्तराखंड के चमोली के कर्ण प्रयाग में स्थित है। यहां पर श्रीहरि विष्णु विराजमान है।
- केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का आठवां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं।
- केदार घाटी में दो पहाड़ हैं- नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी।
- बद्रीनाथ का मंदिर यहां कब से है यह ठीक नहीं मालूम लेकिन जो मंदिर वर्तमान में हैं उसका निर्माण पन्द्रहवीं शताब्दी में रामानुजीय संप्रदाय के स्वामी बदराचार्य के कहने पर गढ़वाल के तत्कालीन नरेश ने कराया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की सुप्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई ने यहां स्वर्ण कलश और छत्री को चढ़ाया। अलकनंदा नदी तट पर स्थापित यह मंदिर 50 फीट ऊंचा है। भगवान के इस क्षेत्र में अनेक गुप्त एवं प्रकट तीर्थ माने जाते हैं।
- रामायण एवं महाभारतकाल से पूर्व भी केदार का अस्तित्व रहा, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या एवं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पाण्डवों को केदार तीर्थ के दर्शन का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मादि देवता भी शिव दर्शन के लिए केदार तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं। आदि शंकराचार्य, विक्रमादित्य और राजा मिहिर भोज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।
- स्कंद पुराण में भगवान शंकर, माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी! यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है, जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया, तभी से यह स्थान मेरा चिर-परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिरनिवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है।
- **पुराणों में हैं उल्लेख** - पुराणों अनुसार भूकंप, जलप्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी।
- भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्यबद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा।
- कहते हैं कि भविष्य में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे तब यही स्थान तीर्थ क्षेत्र होगा। यह स्थान भी चमोली में जोशीमठ के पास सुभैन तपोवन में स्थित है।
- यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल-दर-साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन ब्रद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे।
- चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बदरी, वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है। मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम दो बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए।

अशनीर ग्रोवर की बायोपिक को लेकर इमरान खान ने दी प्रतिक्रिया

आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान जल्द ही फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' से बतौर लीड एक्टर वापसी करने वाले हैं। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें सामने आई थीं कि इमरान बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की बायोपिक में भी नजर आ सकते हैं। बीते दिनों इस बायोपिक से आमिर खान के भी छुड़ने की खबरें सामने आई थीं। अब इमरान खान ने इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है और खबरों के पीछे की सच्चाई से रूबरू करवाया है।

इमरान ने अफवाहों को किया खारिज

इमरान खान ने अशनीर ग्रोवर की बायोपिक में काम करने की खबरों को सिरे से खारिज किया। अभिनेता ने कहा कि मैंने इस परियोजना के बारे में सुना तक नहीं है। यह सच नहीं है। इस प्रतिक्रिया के साथ ही इमरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। वहीं इमरान की प्रतिक्रिया के बाद अब प्रोजेक्ट के अस्तित्व को लेकर भी संदेह पैदा हो रहा है।

आमिर खान के फिल्म से जुड़ने की थीं खबरें

बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थीं कि भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर की बायोपिक बन रही है। इस बायोपिक से आमिर खान के जुड़ने की भी खबरें सामने आई थीं। खबरों में ऐसा दावा किया गया था कि आमिर फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। यानि वो अशनीर ग्रोवर की भूमिका में ही नजर आ सकते हैं। साथ ही ये बताया गया था कि फिल्म को राहुल मोदी निर्देशित कर सकते हैं। उनके द्वारा ही फिल्म की कहानी भी लिखी जाने की खबरें सामने आई थीं। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है। भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर, शार्क टैंक इंडिया में निवेशक के रूप में आने के बाद बेहद लोकप्रिय हो गए।

रकुल प्रीत से शादी को सिचुएशनशिप मानते हैं जैकी भगनानी

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी बी-टाउन के क्यूट कपल में से एक हैं। दोनों अक्सर साथ में कपल गोल देते रहते हैं। हाल ही में जैकी भगनानी ने अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि शादी के बावजूद वह अपने रिश्ते को सिचुएशनशिप की तरह मानते हैं। साथ ही जैकी ने आपस की बॉन्डिंग को लेकर भी बात की।

हाल ही में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने शादी के कारणों और अपने रिश्ते में आए बदलावों के बारे में बात की। जैकी ने बताया कि हमने एक-दूसरे से कहा कि अब हम 20-21 साल के नहीं हैं। हम दोनों ने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से खुशमिजाज इंसान हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहा जो मेरे जीवन की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि अगर मैं उदास रहूंगा, तो चाहे कोई भी मेरे जीवन में आए, मैं उदास ही रहूंगा। तुम भी व्यक्तिगत रूप से खुश हो। साथ में हम और भी खुश हैं। इस पर रकुल ने कहा कि वे एक-दूसरे के जीवन की कमी को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे छुट्टी पर नहीं ले गए, इसलिए मैं दुखी हूं। मैं अकेले भी छुट्टी पर जा सकती हूं। मुझे लगता है कि जीवन में बात करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं।

मैं कुछ भी नहीं छिपाता

इस दौरान जैकी ने कहा कि रकुल और मैं शादीशुदा हैं, लेकिन हमारा रिश्ता एक तरह का सिचुएशनशिप है। इसका मतलब है कि हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि शादी इसी वजह से हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उससे हर बात खुलकर कह सकता हूं। अगर रकुल के आस-पास होने पर मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, तो मैं स्पीकरफोन पर बात करने में जरा भी संकोच नहीं करता। यह जताते हुए कि मैं अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं कुछ भी नहीं छिपाता, इसलिए मुझे घुटन महसूस नहीं होती।

2024 में हुई थी दोनों की शादी

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने 21 फरवरी 2024 को शादी करने से पहले तीन साल तक डेटिंग की। उन्होंने गोवा में एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग की। रकुल और जैकी ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की आधिकारिक तस्वीरें साझा की थीं। शादी में रकुल ने गुलाबी-पीच रंग का लहंगा पहना था, जिस पर ढेर सारे हीरे जड़े हुए थे।

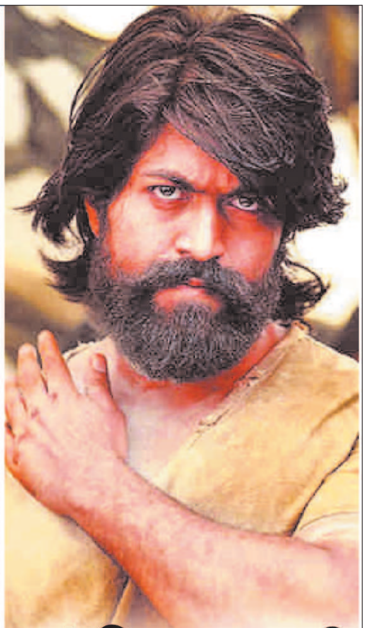

'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले यश ने 'केजीएफ 3' को लेकर दी अपडेट

यश साल की दो मच अवेटेड फिल्मों में नजर आएंगे, इनमें 'टॉक्सिक' और 'रामायण' के नाम शामिल हैं। 'रामायण' में वो रावण के किरदार में नजर आएंगे। इन दो फिल्मों के अलावा फैंस को उनकी 'केजीएफ 3' का भी बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में यश ने 'केजीएफ 3' के भविष्य को लेकर बताया।

सही स्क्रिप्ट का है इंतजार

अमेरिका में सिनेमाकॉन 2026 में 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ अपनी मौजूदगी के दौरान यश ने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इसी दौरान स्क्रीन डेली के साथ बातचीत में यश ने 'केजीएफ 3' के बारे में बात करते हुए कहा कि फिल्म तभी आगे बढ़ेगी जब एक सही स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास 'टॉक्सिक' और 'रामायण 1 और 2' फिल्में हैं। मैं और निर्देशक प्रशांत नील बातचीत करते रहेंगे। हमें सही स्क्रिप्ट चाहिए, उसके बाद हम इसे जरूर बनाएंगे।

2022 में रिलीज हुई थी 'केजीएफ 2'

2022 में रिलीज हुई 'केजीएफ: चैप्टर 2' प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज और अन्य कलाकार प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। रिलीज होने पर 'केजीएफ 2' अब तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म बन गई और इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जो भारत में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।

'टॉक्सिक' में नजर आएंगे यश

वर्कफ्रंट की बात करें तो अब यश अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगे। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

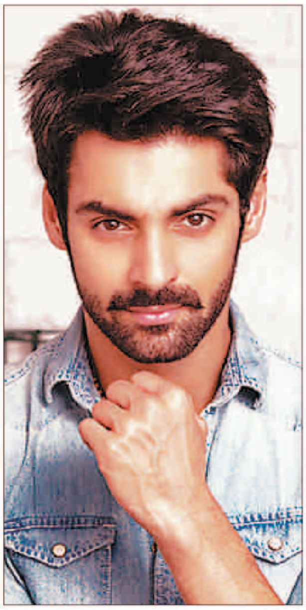

एक्टिंग छोड़ने की खबरों पर करण वाही ने दी प्रतिक्रिया

टीवी से वेब सीरीज का सफर तय करने वाले अभिनेता करण वाही 'रीमिक्स', 'दिल मिल गए', 'नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड' (सीजन 2) और 'चन्ना मेरेया' जैसे कई शो में अभिनय करने के बाद घर-घर में मशहूर हो गए। हाल ही में उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर और जीवन में कुछ देर बाद अपने विश्वासों तक पहुंचने के बारे में खुलकर बात की। सोशल मीडिया पर उनके ये बयान वायरल होने के बाद कई लोगों ने कयास लगाए कि करण अभिनय पूरी तरह छोड़ने वाले हैं। चर्चाओं के बढ़ने के बाद अब अभिनेता ने इसके पीछे की सच्चाई बताई है।

एक्टिंग नहीं छोड़ रहे करण

करण वाही ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट का जवाब दिया, जिसे बाद में हटा दिया गया था। उस पोस्ट में कहा गया था कि अभिनेता ने आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से दूरी बनाने का फैसला किया है। इस पोस्ट को स्टोरी पर साझा करते हुए करण ने कैप्शन में लिखा, 'आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे अपना काम छोड़ना होगा। कृपया वायरल होने के लिए अफवाहें न फैलाएं। संबंधित व्यक्ति से अनुरोध है कि इस पोस्ट को हटा दें और झूठ न फैलाएं। धन्यवाद।'

करण ने कही थी आध्यात्म और नाम जप करने की बात

करण के अभिनय छोड़ने की अटकलें सबसे पहले तब शुरू हुईं जब उन्होंने 'अब्रा का डबरा शो' में बातचीत करते हुए कहा कि लगभग चार-पांच महीने पहले दिल्ली में किसी ने अचानक मुझसे कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे शांत रहना चाहिए और तुलसी की माला पहननी चाहिए। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, लेकिन समय के साथ, किसी कारणवश मैं आध्यात्मिकता से दूर हो गया था। लेकिन पता नहीं पिछले चार-पांच महीने बहुत अच्छे रहे हैं। पता नहीं कैसे, मैं सोचने लगा कि मैं वृंदावन से तुलसी की माला कैसे ला सकता हूं।

इस सीरीज में नजर आए थे करण

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण वाही को हाल ही में सोनी लिव पर स्ट्रीम करने वाली रोमांटिक थ्रिलर सीरीज 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' (2024) में देखा गया था।

राजकुमार राव ने साझा किए बतौर निर्माता पहली फिल्म 'टोस्टर' के अनुभव

अभिनेता राजकुमार राव हाल ही में फिल्म 'टोस्टर' में नजर आए हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ राजकुमार राव ने बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी शुरुआत की है। इस फिल्म को उन्होंने अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जो एक मिडिल क्लास कहानी को कॉमेडी, मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाती है। अब अमर उजाला से खास बातचीत में राजकुमार राव ने प्रोड्यूसर बनने के अनुभव, दोस्ती, शादी की यादों और फिल्म की खासियतों पर खुलकर अपनी बात रखी।

प्रोड्यूसर बनने का अनुभव कैसा रहा और आपने क्या नया सीखा?

मुझे लगता है कि यह मुझे मजबूत बनाने वाला अनुभव है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम है, बहुत मेहनत है। प्रोड्यूसर होना आसान नहीं है। मैं यही सोचता रहा कि पत्रलेखा ने यह सब कैसे मैनेज किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता था कि प्रोड्यूसर का काम बहुत आसान होता होगा। एक बार आपने टीम सेट कर दी, उसके बाद सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चौबीसों घंटे हर दिन आपको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। छोटे भी और बड़े भी। लगातार बातें करनी होती हैं, मीटिंग करनी होती है, बहुत सारा पेपरवर्क होता है। हर चीज के लिए हजारों लोगों से संपर्क रखना पड़ता है, तो काम बहुत ज्यादा होता है। चूंकि, हम दोनों अभिनेता हैं, इसलिए हमें क्रिएटिव चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। एडिट कैसा जा रहा है, डीआई कैसा जा रहा है, साउंड कैसा सुनाई दे रहा है? हर चीज देखनी पड़ती है

पर्दे पर कंजूस किरदार और असल जिंदगी में प्रोड्यूसर, कहीं पैसों का खास ख्याल रखने की प्रैक्टिस तो नहीं चल रही?

यह बिल्कुल एक संयोग है। इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। (हंसते हुए) हम लोग असल जिंदगी में बिल्कुल अलग हैं, कंजूस तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम तो ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो चाहते हैं कि सेट पर लोगों को बहुत अच्छा खाना मिले, सबको समय पर खाना दिया जाए। हम खुद इतने साल से अभिनेता हैं, इसलिए हमें ठीक से पता है कि सेट पर किन चीजों से लोगों को दिक्कत होती है, क्या परेशानियां होती हैं। अगर लोग शिकायत करते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। अगर कोई बात हम तक पहुंचे तो हम उसे तुरंत ठीक करें, क्योंकि हमें खुद पता है कि क्या सही है और क्या गलत।

बतौर प्रोड्यूसर आपने अपनी पहली फिल्म के लिए डार्क कॉमेडी ही क्यों चुनी?

ऐसा कुछ नहीं था। यह पहली चीज थी जो हमारे पास आई थी। इससे पहले भी हमने कुछ और चीजें पढ़ी थीं, लेकिन यह हमें क्लिक हुई। इसे पढ़कर बहुत मजा आया। इसके किरदार और कहानी बहुत दिलचस्प हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे कि यह फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए बने। हमें लगा कि इस ओटीटी प्लेटफार्म पर वहां कॉमेडी कम है, तो यह वैसी फिल्म हो सकती है जिसे ऑडियंस खूब पसंद करें। इसमें एक मिडिल क्लास सोसायटी की कहानी है, जिसे बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाया गया है। कहानी बहुत रियल है, जो इंडियन फॅमिली से जुड़ी हुई है। सब कुछ बहुत फन तरीके से दिखाया गया है। यह एक अलग तरह की फिल्म है, जिसमें मिस्ट्री भी है, थ्रिल भी है और कॉमेडी भी है।

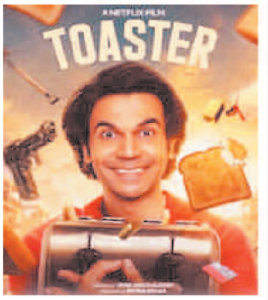

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को तीन माह का चावल दिया जा रहा एकमुश्त

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राज्य शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत जिले के नागरिकों एवं राशनकार्डधारियों की सुविधा को दृष्टिगत सभी पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2026 का तीन माह का चावल एकमुश्त प्रदाय किया जा रहा है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में संचालित सभी 498 उचित मूल्य दुकानों को तीन माह का खाद्यान्न आबंटित कर दिया गया है।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिले की सभी दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण कार्य तीव्र गति से किया गया है, जिसमें कुल आबंटन के विरूद्ध लगभग 75 प्रतिशत भंडारण पूर्ण किया जा चुका है। इसके साथ ही वितरण की स्थिति भी संतोषजनक है। जिले में तीन माह के आबंटन के विरूद्ध लगभग 41 प्रतिशत राशनकार्डधारियों को तीन माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जा चुका है। शेष हितग्राहियों को भी निरंतर वितरण प्रक्रिया के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

जिला खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी द्वारा जिले में भंडारण एवं वितरण की वास्तविक स्थिति के आकलन

करने राजनांदगांव शहर के मोतीपुर, नवागांव, नया ढाबा, राहुल नगर, पुलिस लाईन, स्टेडियम वार्ड के उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हितग्राही उमिर्ला चंद्राकर, देवकी पटेल, मनीषा वर्मा, कमलेश्वरी साहू, टाकेश्वरी साहू, भुवन ढीमर एवं अन्य हितग्राहियों ने बताया कि तीन माह का चावल एकमुश्त मिल हो रहा है। वितरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप से संचालित हो रही है। निरीक्षण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को तीन माह का राशन एकमुश्त वितरण के निर्देश दिये गये। नागरिकों से संबंधित उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार तीन माह का चावल प्राप्त करने की अपील की गई है। वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या या अनियमितता की शिकायत होने पर तत्काल खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 या 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।

30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर प्रजापति ने जारी किया आदेश

मोहला। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। इसके अंतर्गत पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले में नया नलकूप खनन कर सकेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु किए गए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के अनुमति देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व अनुविभाग मोहला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला को एवं राजस्व अनुविभाग मानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

खास खबर

अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, 2 माजदा गाड़ी को किया जप्त

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुमरदा तहसील अंतर्गत ग्राम मोतीपुर नदी घाट में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए रैम्प को तोड़ दिया। साथ ही घाट तक पहुंचने वाले मार्ग को काटकर पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया, ताकि भविष्य में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

इससे पहले टीम द्वारा मोतीपुर नदी घाट से अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे दो माजदा वाहनों को रेत सहित जप्त किया गया। दोनों वाहनों को थाना डोंगरगांव के सुपुर्द कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विजय कोठारी सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर उपस्थित रही।

अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए रैम्प तोड़ा

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज कुमरदा तहसील अंतर्गत ग्राम मोतीपुर नदी घाट में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए रैम्प को तोड़ दिया। साथ ही घाट तक पहुंचने वाले मार्ग को काटकर पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया, ताकि भविष्य में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इससे पहले टीम द्वारा मोतीपुर नदी घाट से अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे दो माजदा वाहनों को रेत सहित जप्त किया गया। दोनों वाहनों को थाना डोंगरगांव के सुपुर्द कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विजय कोठारी सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर उपस्थित रही।

अवैध शराब परिवहन और बिक्री पर की सख्ती मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कलेक्टर तुलिका प्रजापति एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने नशा नियंत्रण और जनसुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर प्रजापति ने आगामी सुशासन तिहार 2026 के दौरान जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतकर्ता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने एन-कॉर्ड की समीक्षा करते हुए जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों से उपचार लेकर लौटे व्यक्तियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि उनका सतत फॉलो-अप के साथ ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे तथा समाज में जागरूकता फैलाने के प्रयास करे। उन्होंने महाराष्ट्र सीमा से अवैध शराब परिवहन पर कड़ी नजर रखते हुए लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने, सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करने तथा मिलावटी शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने जिले के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहां आवश्यक संकेतक एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही यातायात है नियमों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु प्रभावी काययीजना तैयार करने को कहा।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने राजस्व, पुलिस एवं कृषि विभाग समन्वय के साथ कोटवारों एवं ग्राम पंचायत सरपंचों की संयुक्त बैठक आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षण देने की बात कही। उन्होंने अवैध गांजा एवं अफीम की खेती पर रोक लगाने, नशीले पौधों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जी.आर. मरकाम, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव, सहित पुलिस प्रशासन अधिकारी-कर्मचारी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन : सुजल ग्राम संवाद के 6वें संस्करण का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए सुजल ग्राम संवाद के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने जल जीवन मिशन के माध्यम से सोर्स सस्टेनेबिलिटी को लेकर जल संरक्षण के लिए परकोलेसन टैंक, इंजेक्शन वेल, सोख्ता गड्ढा सहित अन्य संरचनाओं के संबंध में जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर से जल संरक्षण के लिए जिले में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।

जल जीवन मिशन अंतर्गत आयोजित सुजल ग्राम संवाद के 6वें संस्करण से डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम बाघमार से पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण शामिल हुए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम में पेयजल व्यवस्था के संबंध में सरपंच उवर्शी ध्रुव एवं जल बहिनीयों के साथ विशेष चर्चा की गई। इस दौरान जल जीवन मिशन से पूर्व ग्राम में पेयजल की स्थिति एवं वतर्मान सुधार, एफ टीके किट के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया, जल संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढा निर्माण का महत्व, जल उपयोग एवं प्रबंधन अंतर्गत वाटर टैक्स के संबंध में जागरूक किया गया। ग्रामवासियों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया।

विधेयक नहीं, कई और कृत्यों के लिए देश की महिलाओं से माफी मांगे मोदी : पिंटू

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत पिंटू ने कहा कि18 अप्रैल को अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन विधेयकों के पैकेज को पारित न करा पाने पर देश की माताओं और बहनों से माफी मांगी। हालांकि बीते कुछ सालों में ऐसे कई मौके सामने आए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का माफी मांगना ज़्यादा उपयुक्त होता।सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि पिछले सप्ताह संसद में विपक्षी दलों द्वारा जिस विधेयक को खारिज किया गया, वह महिला आरक्षण विधेयक 2026 नहीं था, बल्कि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 था। इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना था।लेकिन मोदी सरकार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रही और विधेयक पारित नहीं हो सका। इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी था, जिससे दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के हित प्रभावित होते।इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार यह दावा करते रही कि उसने महिला आरक्षण के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन यह नहीं बताया कि 2023 का वास्तविक महिला आरक्षण विधेयक उसी वर्ष पारित हो चुका था और विपक्ष ने उसका पूर्ण समर्थन किया था।दरअसल, विपक्षी दलों का विरोध इस बात को लेकर था कि सरकार ने महिला आरक्षण को चुपचाप परिसीमन से जोड़ दिया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय टेलीविजन पर विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हमला बोला, जो कि राज्य चुनावों के दौरान सरकारी माध्यमों के उपयोग के नियमों का उल्लंघन माना गया है। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर कन्या भ्रूण हत्या का आरोप लगाया और विशेष रूप से टीएमसी और डीएमके को निशाना बनाया, जिन राज्यों में आगामी सप्ताहों में चुनाव होने वाले हैं।

मोदी ने देश की माताओं और बहनों से माफी भी मांगी और कहा कि एक महिला सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। हालांकि, यदि प्रधानमंत्री अपने इन शब्दों पर अमल करें, तो उन्हें उन घटनाओं के लिए भी माफी मांगनी चाहिए, जिनमें महिलाओं के साथ घोर अन्याय हुआ है। बीते 14 साल में ऐसे कई मौके आए न जब मोदी को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

खाया-पिया और पैसे नहीं दिया, सरकारी दफ्तरों पर कुर्की की नौबत

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

बकाया भुगतान के एक पुराने मामले ने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया, जब न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी कार्यालयों की कुर्की की कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। हालांकि अंतिम समय में समझौते की पहल होने से फिलहाल कार्रवाई टल गई है। मामला खाद्य विभाग द्वारा वर्षों से लंबित भुगतान से जुड़ा है। न्यायालय ने पहले ही वर्ष 2023 में भुगतान करने के निर्देश दिए थे और चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन नहीं होने पर कुर्की की जाएगी। समय मिलने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर अब सख्त कदम उठाए गए।

कार्रवाई के तहत खाद्य विभाग कार्यालय में कम्प्यूटर, टेबल, कुर्सी, पंखे, कूलर और अलमारी जैसे सामानों की सूची बनाकर जब्ती की प्रक्रिया शुरू की गई।

इतना ही नहीं, कलेक्टर न्यायालय के फर्नीचर और उपकरण भी कुर्की की जद में आ गए। इससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बकाया राशि के लिए संबंधित रेस्टोरेंट संचालक अपने वकील और न्यायालय कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान विभाग के अधिकारी मौजूद तो रहे, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में भोरमदेव महोत्सव और अन्य आयोजनों के लिए भोजन सप्लाई का अनुबंध किया गया था, लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया। अब करीब 4.61 लाख रुपये (ब्याज सहित) बकाया है। स्थिति बिगड़ते देख विभाग ने 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मामला सुलझाने की लिखित सहमति दे दी है। इसके बाद फिलहाल कुर्की की कार्रवाई रोक दी गई है।

इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छोटे से भुगतान मामले के इतने लंबे समय तक लंबित रहने और कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई होने से प्रशासन की कायर्शैली पर आलोचना हो रही है।

कलेक्टर ने स्वयं की स्व-गणना, नागरिकों को डिजिटल भागीदारी का दिया संदेश

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जनगणना निदेशालय के निर्देशानुसार जिले में 16 अप्रैल से स्व-गणना शुरू हो गया है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने निर्धारित पोर्टल से अपना स्व-गणना पत्रक ऑनलाइन भरा। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने जिले वासियों से अपील की है कि जनगणना के लिये आने वाले प्रगणकों को सही जानकारी दें। आपके द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रहेगी। स्पष्ट प्रावधान है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होगा।

जनगणना के आंकड़े किसी योजना के हितग्राहियों क्री पात्रता के लिए नहीं बल्कि कल्याणकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य के लिये आधार बनते हैं। बताया गया कि शासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए आसान एवं सरल प्रक्रिया के तहत स्व-गणना भरने की सहूलियत दी गई है। घर का मुखिया इस फार्म को भर सकते है। एक मोबाइल से केवल एक ही स्व-गणना फार्म

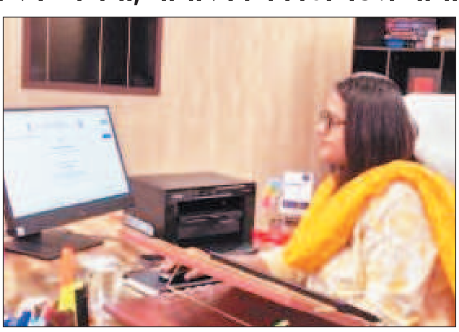

भरा जा सकता है। यह फॉर्म सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भरा जा सकता है। इससे एक आई डी प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर बताना होगा। यदि स्व-गणना फॉर्म नहीं भर पाते तो 1 से 30 मई के बीच प्रगणक घर आकर जानकारी लेंगे।

प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना-भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले में भी दो चरणों में जनगणना होगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) कार्य 01 मई से 30 मई 2026 तक किया जायेगा। जनगणना कार्यक्रम के तहत प्रगणक घर-घर जाकर सेन्सस 2027 हाउस लिस्ट मोबाइल एप का उपयोग कर डिजिटल डाटा संग्रह करेंगे। साथ ही लोगों द्वारा पोर्टल पर स्व-गणना के तहत भरी गई जानकारी का सत्यापन भी करेंगे। दोनों तरह से प्राप्त डाटा की बहुस्तरीय जाँच होगी।

पहले यह कार्य पयर्वेक्षकों द्वारा किया जायेगा। साथ ही चार्ज अधिकारी भी मैदान में जाकर पुनः सत्यापन कर त्रुटियां ठीक करायेंगे। ग्राम व नगर रजिस्टर का प्रारूप व विषय वस्तु, ग्रामीण व नगरीय चार्ज रजिस्टर, प्रगणक, पयर्वेक्षकों व चार्ज अधिकारियों के कार्य, पयर्वेक्षण व कानूनी शक्तियां इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। नागरिकों को स्व-गणना का अवसर प्रदान किया गया है। एसई वेब पोर्टल https://se.census.gov.in/ के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में कोई भी व्यक्ति जनगणना संबंधी निर्धारित बिंदुओं में अपनी जानकारी स्वयं भर सकता है।

ग्राम महरूम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में प्रतिदिन योगाभ्यास का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम महरूम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आयुष में प्रतिदिन योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण योगाभ्यास में शामिल हो रहे है।

इसी क्रम में आज ग्रामीणों को प्रतिदिन विभिन्न योगाभ्यास से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। साथ ही दिनचर्या में नमक, शक्कर तथा तेल की मात्रा कम करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और नियमित योगाभ्यास के लिए शपथ दिलाई गई। योगाभ्यास सत्र में सरपंच उत्तरा सेंडे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रभारी डॉ. प्राजंलि शुक्ला, फार्मासिस्ट छगन मालेकर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रेशमी साहू तथा योग प्रशिक्षक अचर्ना साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भड़का विवाद : धार्मिक हस्तियों पर टिप्पणी से कैंपस में छाया तनाव, जांच शुरू

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

न्यायधानी स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। इस बार मामला विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों से जुड़ा है, जिन पर धार्मिक हस्तियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

व्हाट्सएप चैट से उठा विवाद

जानकारी के अनुसार, लॉ विभाग के कुछ छात्र एक हॉस्टल व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान चैट में भगवान श्री राम को लेकर कथित आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। इसके साथ ही भगवान परशुराम और भीमराव अंबेडकर पर भी अभद्र टिप्पणियां किए जाने की बात सामने आई है।

स्क्रीनशॉट वायरल, भड़का आक्रोश

ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट जैसे ही सोशल मीडिया और अन्य छात्रों तक पहुंचे, मामला तेजी से फैल गया। इसके बाद कैंपस में आक्रोश का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है।

छात्रों का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुट होकर दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इस तरह की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंतरिक जांच समिति गठित कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। साथ ही, पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।

निलंबन या निष्कासन संभव

सूत्रों के अनुसार, यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित छात्रों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निलंबन या निष्कासन जैसे कदम शामिल हैं। फिलहाल प्रशासन और पुलिस दोनों मामले की गहन जांच में जुटे हैं। इस घटना ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है। खासकर विधि के छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून, संवैधानिक मर्यादाओं और सामाजिक संवेदनशीलता को समझते हुए जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें।

4 साल से तालाब सूखा था इस वर्ष पानी ठहरा हुआ और मवेशियों और ग्रामीणों के लिए पानी की सुविधा

जिला प्रशासन ने कंपनियों के साथ अनुबंध कर खरीदी व्यवस्था करने में जुटा

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

छुरिया विकासखंड का ग्राम घुपसाल जनभागीदारी, जल संरक्षण एवं फसल चक्र परिवर्तन के सफल क्रियान्वयन से एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने ग्राम के दौरे के दौरान किसानों एवं स्वच्छता दीदियों को सम्मानित करते हुए ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास, एकजुटता एवं जनशक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि कम पानी वाली फसलों को अपनाने और जल संरक्षण के उपायों के कारण ग्राम में भू-जल स्तर में सुधार हुआ है तथा जल उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, जो अन्य गांवों के लिए प्रेरणास्रोत है।

कलेक्टर ने कहा कि ग्राम घुपसाल ने जिस प्रकार अधिक पानी वाली फसल धान के स्थान पर कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को अपनाया है, वह एक अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में कृषि को टिकाऊ बनाने की दिशा में भी सार्थक कदम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जहां धान की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वहीं मक्का एवं अन्य दलहन-तिलहन फसलों में अपेक्षाकृत बहुत कम पानी लगता है। कलेक्टर ने ग्राम की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि जहां एक परिवार में भी निर्णय लेना कठिन होता है, वहां पूरे गांव द्वारा एकमत होकर फसल परिवर्तन करना ग्राम की जागरूकता और सामाजिक एकता को दर्शाया है। उन्होंने बताया कि ग्राम घुपसाल का यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बन गई है और इसकी सराहना की जा रही है।

कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने ग्रामीणों द्वारा नाला एवं तालाब में पचरी निर्माण की मांग पर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि दीघर्कालीन लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से सोलर पैनल लगाने पर केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे भविष्य में बिजली बिल में कमी आएगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रखने एवं पढ़ाई तथा खेलकूद की ओर प्रेरित करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों के साथ है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही गांवों का समग्र विकास संभव है। ग्राम घुपसाल का यह प्रयास अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव ने कहा कि ग्राम के किसानों एवं महिला स्व-सहायता समूहों ने मिलकर जो कार्य किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पहले जहां अधिक पानी वाली धान फसल के कारण गर्मी में जल संकट उत्पन्न होता था, वहीं अब मक्का एवं अन्य कम पानी वाली फसलों के कारण गांव में पर्याप्त जल उपलब्ध है। यह परिवर्तन ग्रामीणों की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। ग्राम घुपसाल का यह प्रयास न केवल जिले, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने सभी ग्रामीणों को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार मिल-जुलकर कार्य करने की अपील की।

पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव ने सराहना करते हुए कहा कि ग्राम घुपसाल में जल संरक्षण एवं फसल चक्र परिवर्तन अभियान की ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल किसी एक व्यक्ति, अधिकारी या संस्था का नहीं, बल्कि पूरे गांव, किसानों, महिला समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा जिला एवं जनपद प्रशासन के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज के समय में धन, संसाधन और सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। ग्राम घुपसाल ने जनभागीदारी के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सामूहिक संकल्प से बड़े से बड़े कार्य संभव हैं।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम के किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पहले ग्राम में पानी की बहुत समस्या होती थी। लेकिन इस वर्ष धान की जगह मक्का एवं दलहन-तिलहन फसल लेने से पानी की समस्या नहीं हो रही है। किसानों ने बताया कि पूर्व में गर्मी के मौसम में भू-जल स्तर नीचे चले जाने से सूखे जैसी स्थिति बन जाती थी। मार्च माह के बाद गांव के तालाब, हैंडपंप एवं नालों में पानी नहीं रहता था, जिससे पेयजल एवं निस्तारी की गंभीर समस्या उत्पन्न होती थी।

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के सामूहिक प्रयास एवं महत्वपूर्ण निर्णय से इस वर्ष लगभग 350 एकड़ से अधिक रकबे में रबी मौसम में मक्का एवं अन्य दलहन-तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों का उत्पादन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्राम में भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है तथा पेयजल एवं निस्तारी कार्यों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जहां पूर्व में फागुन माह के बाद तालाब सूख जाते थे, वहीं इस वर्ष अभी भी निस्तारी के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, सीईओ छुरिया होरी लाल साहू, सरपंच नरेश शुक्ला, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान उपस्थित थे।

दुर्ग पुलिस में 4 एएसआई बने उप निरीक्षक, एसएसपी ने लगाए स्टार—मनोबल बढ़ने की उम्मीद

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग पुलिस में चार सहायक उप निरीक्षकों को पदोन्नत कर उप निरीक्षक बनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पदोन्नत अधिकारियों को स्टार अलंकरण लगाकर शुभकामनाएं दीं और नई जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हुए जनसेवा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने का संदेश दिया।

छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के आदेश के तहत यह पदोन्नति की गई है। समारोह के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि पदोन्नति से पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और इससे अधिकारियों में बेहतर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी अधिकारी अपने नए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, अनुशासन और जवाबदेही के साथ करेंगे।

पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों की अब तक की सेवाओं और कायर्शैली की सराहना करते हुए उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

पदोन्नत अधिकारियों ने भी इस अवसर पर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण दोहराया और भरोसा दिलाया कि वे जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। पदोन्नति प्राप्त अधिकारीः गोरख नाथ चौधरी, पूर्ण बहादुर कांकी, चन्द्रशेखर सोनी और केशव दयाल तिवारी शामिल हैं। इस पदोन्नति को पुलिस विभाग में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि फील्ड स्तर पर पुलिसिंग भी और मजबूत होगी।

घुनघुट्टा नदी में डूबे मामा-भांजी, बचाने की कोशिश बनी जानलेवा

नई दृष्टिबिंदु / अंबिकापुर

सरगुजा जिले की घुनघुट्टा नदी में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। 12 वर्षीय बालिका और उसे बचाने के लिए नदी में कूदे उसके मामा—दोनों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है।

नहाने के दौरान बिगड़ा संतुलन

जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर के नमना कला निवासी ईश्वर सोनी की 12 वर्षीय पुत्री सिन्नी सोनी गर्मी की छुट्टियों में रायपुर से अपने घर आई हुई थी। शनिवार शाम परिवार के साथ वह घुनघुट्टा नदी घूमने गई थी। करीब साढ़े 5 बजे वह नहाने के लिए नदी में उतरी, तभी अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी।

भांजी को बचाने कूदे मामा, दोनों समाए पानी में

भांजी को डूबता देख मामा विनीत सोनी ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। लेकिन नदी का तेज बहाव और गहराई दोनों पर भारी पड़ गई। देखते ही देखते दोनों पानी में समा गए। मौके पर मौजूद परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला और तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ही घटना में मामा-भांजी की मौत से पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें।

जुआ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कारेवाई, दो मामलों में 7 जुआरी गिरफ्तार

खैरागढ़। छुईखदान थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला केसीजी पुलिस ने अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कुल ?4650 की नगद राशि और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पुरेना में स्कूल के पास मैदान में कुछ लोग 52 पत्ती ताश के माध्यम से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं और पैसों का दांव लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए रेड कार्रवाई की। कार्रवाई में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें जीतलाल जंघेल (28 वर्ष), लेखराम घुरवे (36 वर्ष) और सूयर्कांत चंदेल (42 वर्ष) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सुशासन का स्वर्णिम अध्याय : दक्ष वैद्य

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी एवं हिन्द सेना युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्ष वैद्य साहू ने प्रदेश के यशस्वी, संवेदनशील एवं कमयीगी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान हेतु विशेष हेल्पलाइन प्रारंभ करने के दूरदर्शी निर्णय का स्वागत किया है। साहू ने कहा कि यह हेल्पलाइन 'अंत्योदय' से 'सवीदय' तक की यात्रा को साकार करने वाला सेतु है। यह केवल एक फोन नंबर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की 'जनता ही जनार्दन' की भावना का जीवंत प्रमाण है। अब सुदूर अंचल का अन्नदाता किसान हो या स्वरोजगार की राह देखता युवा, नारी सशक्तिकरण को आकांक्षी बहन हो या वृद्धावस्था पेंशन की प्रतीक्षा करता बुजुर्ग - हर व्यक्ति अपनी बात बिना किसी बाधा, बिचौलिए या विलंब के सीधे शासन के शीर्ष तक पहुंचा सकेगा।

दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सेवा ही संगठन, सुशासन ही संकल्प' के मंत्र को जिस दृढ़ता से धरातल पर उतारा है, यह हेल्पलाइन उसका स्वर्णिम उदाहरण है। फसल बीमा, खाद-बीज, सिंचाई, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था अथवा महिला सुरक्षा से जुड़ा कोई भी विषय अब एक कॉल पर दर्ज होगा और समयबद्ध, जवाबदेह प्रणाली से उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। साहू ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में जनता अपनी फरियाद लेकर कार्यालयों के चक्कर काटती थी, परंतु आज डबल इंजन की भाजपा सरकार स्वयं जनता के द्वार पर दस्तक दे रही है। यही 'जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार' का वास्तविक स्वरूप है।

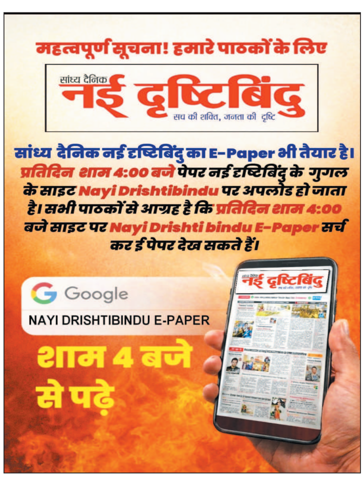

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100